अब वेब पर भी www.rashtriyaprastavana.com
उत्तर प्रदेश (लखनऊ व कानपुर) से एक साथ प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र
आर.एन.आई. नं.-यूपीएचआईएन/2011/37605

दैनिक राष्ट्रीय प्रस्तावना

गाँव से गवर्नेन्स तक

लखनऊ, रायबरेली, इलाहाबाद, आजमगढ़, अयोध्या, झांसी, अम्बेडकरनगर, एटा, औरैया, अमेठी, फतेहपुर, बांदा, उन्नाव, लखीमपुर, मुरादाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, सीतापुर, जौनपुर, श्रावस्ती, उरई, जालौन, फिरोजाबाद, हरदोई, मथुरा, कानपुर, ललितपुर, गोण्डा, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, सन्तकबीरनगर, नोयडा, सुलतानपुर, कासगंज सहित प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में बहुप्रसारित

वर्ष : 15 अंक 136 लखनऊ, रविवार, 30 नवम्बर 2025 पृष्ठ: 8 मूल्य : 2.00

संक्षिप्त

शीतकालीन सत्र में भी सुनाई देगी एसआईआर की गूंज

नई दिल्ली। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्ष के मौजूदा तेवरों को देखते हुए संसद के शीतकालीन सत्र में भी इसके छाये रहने की संभावना है। इस सत्र में विपक्ष दिल्ली कार विस्फोट, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या और नये श्रम कानूनों जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठायेगा। विपक्ष और सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संक्षिप्त सत्र के लिए कमर कस ली है और दोनों पक्ष अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। शीतकालीन सत्र एक दिसम्बर से 19 दिसम्बर तक चलेगा और इस दौरान केवल 15 बैठकें होंगी।

नौसेना को मिला नीलगिरी श्रेणी का चौथा स्वदेशी एडवांस्ड स्टेल्थ फ्रिगेट 'तारागिरी'

नई दिल्ली। मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड (एमडीएल) में निर्मित नीलगिरि श्रेणी का चौथा युद्धपोत तारागिरी, मुंबई में शनिवार को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। प्रोजेक्ट 17 ए के तहत बनाया गया यह युद्धपोत डिजाइन और निर्माण में आत्मनिर्भरता पाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। यह फ्रिगेट कई तरह से इस्तेमाल होने वाले मल्टी-मिशन प्लेटफॉर्म हैं, जिन्हें समुद्री क्षेत्र में मौजूदा और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह युद्धपोत प्रोजेक्ट-17 अल्फा फ्रिगेट्स (पी-17ए) का हिस्सा है, जो गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट्स का एक वर्ग है, जिसका निर्माण वर्तमान में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (एमडीएल) और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) में नौसेना के लिए किया जा रहा है।

अब यूपी में नहीं होती गुंडागर्दी, नहीं चलता माफियाराज : मुख्यमंत्री

● मुख्यमंत्री योगी ने किया 408 करोड़ रुपये के 114 विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के अंदर लाखों युवाओं को उनके गृहक्षेत्र में ही नौकरी और रोजगार देने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर कार्य प्रारंभ किए हैं। इसके लिए सरकार ने काफी प्रयास किए। सुरक्षा का ऐसा बेहतर वातावरण बनाया जहां गुंडागर्दी नहीं चलती। गुंडा टैक्स, माफियाराज, मनमानापन नहीं चलता। अपराध और अपराधियों के प्रति तथा भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाती है। जीरो टॉलरेंस, केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि भाव भी है, जिसे जमीनी धरातल पर सख्ती के साथ उतारा गया। इसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज कानून-व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से देश के अंदर एक मॉडल स्टेट के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने में सफल हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश से माफिया गायब हैं। कर्फ्यू गायब, दंगे बंद, अराजकता बंद है। उपद्रव का प्रदेश अब उत्सव का प्रदेश बन गया है। मुख्यमंत्री योगी शनिवार को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के 36वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। भव्य और विविधतापूर्ण समारोह में मुख्यमंत्री ने गीडा के विभिन्न सेक्टरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 408 करोड़ रुपये के 114 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 6139 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के लिए आवंटित 115 भूखंडों में से पांच निवेशकों को अपने हाथों से आवंटन प्रमाण पत्र सौंपा।

विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आंतरिक सुरक्षा अपरिहार्य : प्रधानमंत्री

● डीजीपी -आइजी कॉन्फ्रेंस में कानून व्यवस्था और आतंकवाद पर रोडमैप तैयार

एजेंसी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के आईआईएम परिसर में डीजीपी-आइजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि विजन 2047 के तहत विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आंतरिक सुरक्षा अपरिहार्य है।

दूसरे दिन शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में कानून व्यवस्था व आतंकवाद पर रोडमैप तैयार किया गया। इसमें नक्सलवाद, काउंटर टेररिज्म, महिलाओं की सुरक्षा, एआई जांच पर फोकस किया गया। विजन 2047 के तहत सुरक्षा की चर्चा और थानों की रैंकिंग घोषित हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने डीजीपी-आईजीपी को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारी पुलिस बल को आधुनिक तकनीक से लैस करना होगा ताकि अपराध और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा सके।कॉन्फ्रेंस में 16,000 से अधिक थानों की उत्कृष्टता रैंकिंग भी घोषित की गई, जिसमें मध्य प्रदेश के मंदसौर थाने को टॉप-10 में स्थान मिला।महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष सत्र में पीएम ने 'मिशन शक्ति' को मजबूत करने का आह्वान किया।

छत्तीसगढ़ नवा रायपुर में आयोजित 60वीं अखिल भारतीय डीजीपी-आईजीपी कॉन्फ्रेंस में देश की सुरक्षा का रोड मैप पेश किया। देश की कानून व्यवस्था को मजबूत करने और आतंकवाद से निपटने के लिए व्यापक चर्चा हुई।

चुनाव आयोग ने ऐप ईसीआईनेट को बेहतर बनाने को मांगे सुझाव

एजेंसी

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने सभी नागरिकों को ईसीआईनेट ऐप डाउनलोड करने और ऐप पर 'सुझाव जमा करें' टैब का उपयोग करके ऐप को बेहतर बनाने के लिए सुझाव आमंत्रित किया है। यह 27 नवंबर से 27 दिसंबर के बीच किया जा सकता है। ईसीआईनेट ऐप के परीक्षण संस्करण का उपयोग बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और हाल के उपचुनावों के दौरान किया गया था। इस नए मंच ने बेहतर मतदाता सेवाओं, मतदान प्रतिशत दर रुझानों की त्वरित उपलब्धता और मतदान समाप्त होने के 72 घंटों के भीतर अनुक्रमणिका कार्डों के प्रकाशन को भी सक्षम बनाया। मंच की कार्यक्षमता को और बढ़ाना के लिए बिहार चुनावों से मिली सीख और सीईओ, डीईओ, ईआरओ, पर्यवेक्षकों और क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया को शामिल किया जा रहा है। उपयोगकर्ता के सुझावों की जांच की जाएगी और प्लेटफॉर्म को और अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए इसे और अद्यतन किया जाएगा।

ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म का आधिकारिक शुभारंभ जनवरी 2026 में करने की योजना है। मतदाताओं की सुविधा में सुधार और प्रौद्योगिकी के उपयोग से चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ईसीआईनेट मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ आयोग की प्रमुख पहलों में से एक है।

लखनऊ में बीजेपी का नया हाईटेक दफ्तर बनेगा

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

● 200 करोड़ से अधिक की लागत, 58 हजार वर्गफीट में फैली विशाल इमारत

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का नया, अत्याधुनिक और भव्य प्रदेश कार्यालय जल्द ही निर्माण के चरण में प्रवेश करेगा। जियामऊ की 58 हजार वर्गफीट जमीन पर बनने वाले इस भवन की लागत 200 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। इसके डिजाइन और लेआउट को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार शाम 5 बजे अपने सरकारी आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के अलावा संगठन व निर्माण समिति से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की पहल पर पूरे देश में भाजपा के जिला और प्रदेश कार्यालयों के निर्माण और आधुनिकीकरण का अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश के 98 संगठनात्मक जिलों में से अब तक 90 कार्यालय पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि झांसी, उरई और चित्रकूट में निर्माण कार्य जारी है। गाजियाबाद, मऊ और गोरखपुर में कार्यालयों के लिए जमीन की तलाश की जा रही है।

नई इमारत का निर्माण लोहिया पथ पर किया जाएगा, जो राजनीतिक दृष्टि से राजधानी की प्रमुख लोकेशन मानी जाती है। यह कार्यालय प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों में सबसे बड़ा और आधुनिक होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि नए भवन का नक्शा और डिजाइन दिल्ली से तैयार कराया गया है। बैठक में इसी पर अंतिम मुहर लगेगी।

कदम-कदम पर सीसीटीवी, पूरी तरह हाईटेक इमारत

नया कार्यालय तकनीक और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर अत्याधुनिक सुविधाओं का संगम होगा। प्रवेश से निकलने तक हर व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगा। भवन में विभिन्न पदाधिकारियों और मंत्रियों के अलग-अलग कक्ष बनाए जाएंगे। कार्यालय में होंगे-4 से 5 बड़े-छोटे मीटिंग हॉल,1000 लोगों की क्षमता वाला विशाल ऑडिटोरियम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, डिजिटल वॉर रूम, कॉल सेंटर व हाईटेक आईटी सेल, चुनाव मैनेजमेंट रूम, लाइब्रेरी और बड़ी भोजनशाला, करीब 50 लोगों के ठहरने के लिए गेस्ट हाउस, बेसमेंट में पार्किंग की विस्तृत व्यवस्था, भवन का निर्माण कार्य पूरा होने में लगभग 3 वर्ष लगेंगे।

ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

मौजूदा भाजपा कार्यालय में बड़ी बैठकों के दौरान विधानसभा मार्ग पर अक्सर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। नए कार्यालय के बाद इस समस्या से राहत मिलेगी। साथ ही बड़े राजनीतिक आयोजनों के लिए अब पार्टी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जैसी जगहों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

नया भवन तैयार होने के बाद भी विधानसभा मार्ग स्थित भाजपा का मौजूदा प्रदेश कार्यालय चलता रहेगा। हाल ही में राज्य संपत्ति विभाग ने इसके बगल के एक सरकारी आवास को भी पार्टी को आवंटित किया है। भाजपा की योजना है कि भविष्य में इस परिसर को भी और विकसित कर भव्य स्वरूप दिया जाए। नए और आधुनिक कार्यालय की स्थापना से भाजपा की संगठनात्मक गतिविधियों को गति मिलेगी और राजधानी लखनऊ में पार्टी की कार्यक्षमता और दायरा दोनों में उल्लेखनीय विस्तार होगा।

'वन नेशन, वन इलेक्शन'-अब बस एक कदम दूर!

संविधान संशोधन से बदले जा सकते हैं लोकसभा-विधानसभाओं के कार्यकाल

● एक साथ चुनाव पर विधि आयोग की बड़ी रिपोर्ट

● 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के लिए संशोधन का रास्ता खुला

● लोकसभा-विधानसभा की अवधि में बदलाव प्रस्तावित

● अनुच्छेद 83(2) और 172(1) में संशोधन की जरूरत

● एक साथ चुनाव से खर्च और बाधाएं कम होंगी

मनोज शुक्ला

'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लेकर देश में सियासी बहस जारी है। इसी बीच भारत के विधि आयोग ने अहम जानकारी दी है। आयोग ने संसद की संयुक्त समिति को स्पष्ट किया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के पांच साल के कार्यकाल को बदलने के लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यह संशोधन 'वन नेशन, वन इलेक्शन' जैसे अहम राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। देश में लंबे समय से जारी 'वन नेशन, वन इलेक्शन' की बहस अब निर्णायक मोड़ पर पहुँचती दिख रही है। भारत के विधि आयोग ने संसद की संयुक्त समिति को महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के पाँच वर्ष के कार्यकाल में संविधान संशोधन के जरिए बदलाव किया जा सकता है। आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि राष्ट्रीय हित की आवश्यकता हो, तो संसद के पास यह बदलाव करने की पूरी शक्ति है।

भारत के विधि आयोग ने संसद की संयुक्त समिति को बताया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के पाँच वर्ष के कार्यकाल में बदलाव संविधान संशोधन के माध्यम से पूरी तरह संभव है। आयोग के अनुसार, यदि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' जैसा राष्ट्रीय उद्देश्य लागू करना है, तो अनुच्छेद 83(2) और 172(1) में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं, जिससे एकसमान चुनावी चक्र स्थापित हो सके।

संविधान क्या अनुमति देता है?

विधि आयोग ने बताया कि भारतीय संविधान संसद को कार्यकाल में परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान करता है। यह संशोधन उन परिस्थितियों में किया जा सकता है, जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों की बचत, राजनीतिक स्थिरता, और लगातार होने वाले चुनावों से जुड़े प्रशासनिक बोझ को कम करना आवश्यक हो। आयोग ने कहा कि एकसाथ चुनाव होने पर सरकारी मशीनरी पर पड़ने वाला दबाव काफी हद तक कम हो सकता है।

किन अनुच्छेदों में बदलाव आवश्यक?

वर्तमान स्थिति में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः अनुच्छेद 83(2) और 172(1) के तहत पाँच वर्ष निर्धारित है। विधि आयोग के अनुसार, इन दोनों अनुच्छेदों में संशोधन कर चुनावों का चक्र एकसमान बनाया जा सकता है – यानी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय आयोजित किए जा सकते हैं।

लगातार चुनावों से बढ़ रहा बोझ

आयोग ने समिति को बताया कि लगभग हर वर्ष देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव होते रहते हैं। इससे सरकारी मशीनरी, सुरक्षा बल और प्रशासन लगातार व्यस्त रहते हैं। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता बार-बार लागू होने से विकास कार्यों की गति रुकती है। आयोग का मानना है कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन'' से इन रुकावटों में कमी आएगी और चुनावी खर्च में भी भारी कटौती संभव है।

संयुक्त समिति का कार्य और अगला कदम

सरकार द्वारा गठित संयुक्त समिति 'वन नेशन, वन इलेक्शन' की व्यवहारिकता, संवैधानिक आवश्यकता और राजनीतिक सहमति का अध्ययन कर रही है। विधि आयोग की विस्तृत जानकारी मिलने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट जल्द संसद को सौंपेगी। माना जा रहा है कि समिति की सिफारिशें सकारात्मक रहीं तो केंद्र सरकार संविधान संशोधन बिल लेकर आ सकती है।

क्या हो सकता है आगे का बदलाव?

यदि सभी राजनीतिक दलों में सहमति बनती है, तो देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। इससे न केवल चुनावी खर्च कम होगा, बल्कि प्रशासनिक रुकावटें भी घटेंगी और शासन में स्थिरता आने की उम्मीद है।

राजनीतिक मतभेद अभी भी बरकरार

हालांकि इस प्रस्ताव पर सहमति बनना उतना आसान नहीं है जितना दिखाई देता है। कई विपक्षी दलों और संवैधानिक विशेषज्ञों ने राज्यों के अधिकारों, संभावित राजनीतिक अस्थिरता और संवैधानिक जटिलताओं को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि अगर किसी राज्य में सरकार समय से पहले गिरती है, तो पूरा चुनावी कैलेंडर गड़बड़ा सकता है।

सुधार का बड़ा अवसर, लेकिन चुनौतियाँ भी

कुल मिलाकर, विधि आयोग की राय को सरकार और समिति दोनों ही गंभीर संकेत मान रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद संसद में बड़ा संवैधानिक संशोधन देखने को मिल सकता है, जो आने वाले वर्षों में भारत की चुनाव प्रणाली को पूरी तरह बदल सकता है।

बरेली में एसआईआर ने 40 साल बाद सलीम को बनाया ओमप्रकाश

बरेली। देश भर में चर्चा का विषय बने मतदाता गहन निरीक्षण (एसआईआर) ने एक परिवार को अपनों से मिलवा दिया। दरअसल, 40 साल पहले घर से नाराज होकर निकले ओमप्रकाश दिल्ली में मुसलमान बन गए। अब जब दिल्ली में एसआईआर सर्वे हुआ तो वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था, जिस वजह से वो अपने बरेली जिला शाही गांव वापिस आ गए। गांव पहुंचते ही ग्रामीणों ने फूल-मालाओं, बैंड-बाजे और जुलूस साथ उनका भव्य स्वागत किया। बरेली शाही थाना क्षेत्र काशीपुर निवासी ओमप्रकाश आखिरकार अपने घर वापिस लौट आए। काशीपुर निवासी ओमप्रकाश पुत्र वेद राम मात्र 15 वर्ष की उम्र में घर से नाराज़ होकर चले गए थे।

रेल मंत्री ने जैसलमेर में नई सुपरफास्ट ट्रेन स्वर्णनगरी एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी

● अश्विनी वैष्णव ने बॉर्डर के इलाकों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की महत्वपूर्ण योजना का किया ऐलान

एजेंसी

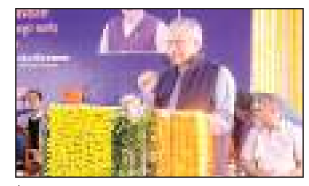

जोधपुर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को जैसलमेर में नई सुपरफास्ट रेल सेवा स्वर्णनगरी एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही राज्य के बॉर्डर इलाकों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की महत्वपूर्ण योजना का ऐलान भी किया। रेल मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान के सभी बॉर्डर इलाकों तक मजबूत रेल कनेक्टिविटी पहुंचे, ताकि सुरक्षा व्यवस्था और नागरिकों की आवाजाही दोनों में मजबूती आए।

रेल मंत्री ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और भीलड़ी जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों को एक नई रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना का डीपीआर तैयार किया जा रहा है और कुछ ही महीनों में इसका प्रारूप अंतिम रूप ले लेगा। इस नेटवर्क के बनने से न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को बल मिलेगा, बल्कि इन इलाकों के आर्थिक और सामाजिक विकास की नई राह भी खुलेगी। कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बॉर्डर क्षेत्रों में रेल लाइन का विस्तार केवल विकास का साधन नहीं, बल्कि यह देश की सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। सीमावर्ती जिलों में तेज और सुरक्षित रेल संपर्क सेना की तैनाती, लॉजिस्टिक्स और राहत कार्यों को समय पर पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। राजस्थान में वर्तमान समय में करीब 55 हजार करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट संचालित हैं और 85 रेलवे स्टेशनों को नए रूप में विकसित किया जा रहा है।

श्रीलंका में भारत ने शुरू किया ऑपरेशन 'सागर बंधु'

● वायु सेना ने 21 टन राहत सामग्री एयरलिफ्ट की और नौसेना ने समुद्र के रास्ते राहत सामग्री कोलंबो पहुंचाई

एजेंसी

नई दिल्ली। श्रीलंका में चक्रवात दित्वा के कारण भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है और 43,991 लोग प्रभावित हुए हैं। खराब मौसम से उड़ानें और रेल सेवाएं ठप हैं, इसलिए भारत ने वायु सेना और नौसेना के माध्यम से ऑपरेशन 'सागर बंधु' शुरू किया है, जिसके तहत श्रीलंका में मदद भेजी गई है। वायु सेना ने 21 टन राहत सामग्री के साथ 80 से ज्यादा एनडीआरएफ कर्मियों और 8 टन सामान कोलंबो पहुंचा दिया है। इसी तरह नौसेना ने आईएनएस विक्रांत और युद्धपोत उदयगिरि से राहत सामग्री कोलंबो में श्रीलंकाई अधिकारियों को सौंपी है। चक्रवात 'दित्वा' की वजह से हुई तबाही को देखते हुए वायु सेना ने 28/29 नवंबर की रात को हिंडन एयर बेस से एक सी-130 और एक आईएल-76 को तुरंत तैनात किया। इस चक्रवात की वजह से भारी बारिश से पूर्वी श्रीलंका में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार के आदेश पर 80 बचावकर्मियों वाली दो टीमों को श्रीलंका में बचाव और राहत काम के लिए भेजा गया है। हिंडन एयर बेस से आज सुबह 04:06 बजे आईएल-76 से उड़ान भरी और 08:10 बजे कोलंबो में लैंड किया। इसके अलावा लगभग 21 टन राहत सामग्री प्रभावित देश में भेजी गई हैं, जिसमें टेंट, कंबल, गद्दे, डिग्निटी किट और दूसरी चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा सी-130? परिवहन विमान से 21 टन राहत सामग्री और 80 से ज्यादा एनडीआरएफ कर्मियों के साथ 8 टन का सामान पहुंचाया है। वायु सेना ने शनिवार को बताया कि चक्रवात से हुई भारी तबाही के बाद भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है, जिसमें प्रभावित समुदायों की मदद के लिए जरूरी राशन और जरूरी सप्लाई पहुंचाई गई है।

गांवों में जल प्रवाह के लिए नालियों एवं आंतरिक सड़कों का निर्माण प्राथमिकता से करें : केशव प्रसाद मौर्य

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। गांवों में पानी की निकासी के लिए नाली एवं पर्याप्त सड़कों का होना ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। कहीं–कहीं वर्षा ऋतु में जल भराव की समस्या गंभीर हो जाती है, जिससे ग्रामीणों को असुविधा होती है। ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त आंतरिक गलियां उपलब्ध हों और भराव/जल प्लावन की स्थिति बिल्कुल भी न हो, इसके लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामों में जलभराव की समस्या के निदान के लिए नाली एवं नागरिक सुविधाओं हेतु आंतरिक सड़कों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मनरेगा गाइड लाइन में निहित प्राविधानों के तहत यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जांय।

ग्राम्य विकास आयुक्त जी. एस. प्रियदर्शी ने बताया कि शासन की ओर से सभी जिलाधिकारियों-जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) को समय-समय पर जारी शासनादेशो-दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत मनरेगा एवं राज्य वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त/14वां वित्त आयोग की धनराशि को अभिसरण कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना के अनुरूप कार्यस्थलों का चिन्हांकन करके आवश्यकतानुसार पक्का खड़ंजा-नाली निर्माण कार्य कराये जाए। मनरेगा आपरेशनल गाइडलाइन व मास्टर सर्कुलर का उल्लेख करते हुए मनरेगा गाइडलाइन के अनुसार कार्य कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। यह भी इंगित किया गया है कि मनरेगा में श्रम सामग्री अनुपात 60:40 प्राविधानित होने के कारण सामग्री मद सीमित ही रहेगा। इस सामग्री मद में नागरिक सुविधाओं के लिए आंतरिक सड़कों एवं जल प्रवाह के लिए नालियों का बनाया जाना प्राथमिकता पर वांछनीय है।

दिव्यांग महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है योगी सरकार

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में दिव्यांग महिलाओं का सशक्तिकरण को नया आयाम मिला है। एक ओर तो प्रदेश में केंद्र सरकार की 'सुगम्य भारत अभियान' और डिजिटल इंडिया' की साझा लहर ने दिव्यांगजनों, विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो वहीं दूसरी ओर योगी सरकार के डिजिटल साक्षरता अभियान और समावेशी अवसरों ने उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 से ही राज्य में दिव्यांगों के लिए बढ़े हुए 4 प्रतिशत आरक्षण को लागू किया था। इससे दिव्यांगजनों के लिए 3 लाख से अधिक नौकरियों का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसमें दिव्यांग महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से पहले दिव्यांगजनों की स्थिति दयनीय थी।

गैंग लीडर की 98.44 लाख की अवैध सम्पत्ति कुर्क

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिनहट थाना और बीबीडी पुलिस टीम ने शनिवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गैंग लीडर कुलदीप सिंह की 98.44 लाख की चल-अचल संपत्ति जब्त की हैं।

चिनहट थाना प्रभारी दिनेश चन्द्र मिश्र ने बताया कि यह कार्रवाई संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) के निर्देश 21 नवंबर को पारित आदेश के अनुपालन में की है। कुर्की की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस ने कुलदीप सिंह के राधापुरम कॉलोनी, कंचनपुर मटियारी स्थित घर के बाहर आवश्यक सूचना वाला नोटिस बोर्ड भी लगाया, जिसमें साफ चेतावनी दी है कि संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कब्जा, उपयोग या अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त कुलदीप सिंह पर 2023 में पीड़ित राम मिलन की बहु पूजा यादव की हत्या, धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार कराने और आर्थिक लाभ अर्जित करने का गंभीर मामला दर्ज है। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है।

बीबीडी थाने की संयुक्त टीम ने चिनहट थाना प्रभारी दिनेश चन्द्र मिश्र के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए चिन्हित संपत्ति को कब्जे में लिया और मौके पर बोर्ड लगाकर कुर्की की घोषणा सार्वजनिक की।

उत्तर प्रदेश में सड़कों को गढ्ढा मुक्त करने के लिए नई तकनीक आज़माएगी योगी सरकार

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार अब सड़कों पर बार-बार होने वाली गड्ढों की समस्या से स्थायी राहत दिलाने की दिशा में एक नई तकनीक आज़माने जा रही है। अधिकारियों की मानें तो राज्य में पहली बार प्री-कास्ट कंक्रीट ब्लॉकों से सड़क बनाने का परीक्षण किया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए 29 नवंबर को यूपी पीडब्ल्यूडी और आईआईटी-कानपुर के विशेषज्ञ संयुक्त बैठक में ट्रायल की रूपरेखा और स्थान तय करेंगे।

पीडब्ल्यूडी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित तकनीक के तहत सड़क पर पहले से तैयार कंक्रीट ब्लॉकों को मशीनरी और क्रेनों की मदद से बिछाया जाएगा। यह ब्लॉक पारंपरिक बिटुमेन-कोलतार मिश्रण की जगह सड़क की सतह बनाएंगे। पीडब्ल्यूडी ने वर्ष 2025 में गड्ढा-मरम्मत के लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जबकि अधिकारियों का मानना है कि यदि यह तकनीक सफल रहती है, तो हर साल की यह बड़ी लागत बचाई जा सकेगी।

अधिकारियों के मुताबिक़ चयनित सड़क खंड पर इस नई पद्धति का ट्रायल निर्माण किया जाएगा। यदि परिणाम सकारात्मक रहे तो राज्य सरकार इसे नई सड़कें बनाने, नियमित मरम्मत और विशेष मरम्मत सभी में लागू करने की योजना बना रही है।

यूपी पीडब्ल्यूडी के विकास प्रमुख और अभियंता अशोक के. द्विवेदी ने बताया कि कंक्रीट ब्लॉक सड़कें कई फायदे प्रदान करती हैं और यदि ट्रायल सफल रहा तो इन्हें सड़क निर्माण प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। तकनीक में अलग से ब्लॉक निर्माण केंद्र, सड़क बेस की ड्रेनेज और आवश्यक आकार-मोटाई के ब्लॉकों की स्थापना शामिल है।

द्विवेदी ने बताया कि पहले सड़कें बनाने के बाद कम से कम एक दिन तक ट्रैफिक रोकना पड़ता है और कंक्रीट सड़कों को 21 दिन की 'क्योरिंग' चाहिए होती है, वहीं कंक्रीट ब्लॉक सड़कें बिछाते ही यातायात के लिए खोल दी जा सकती हैं। सतह को क्लैंप की मदद से सुरक्षित किया जाता है। आईआईटी-कानपुर इस बैठक में महाराष्ट्र में आईआईटी-बॉम्बे के सहयोग से बनी एक समान सड़क का अनुभव भी साझा करेगा।

अधिकारियों ने बताया कि पेट्रोलियम-आधारित बाइंडर से बनी बिटुमेन सड़कें तेज बारिश और भारी यातायात के दबाव में जल्दी खराब हो जाती हैं, जबकि कंक्रीट ब्लॉक सड़कें अधिक टिकाऊ होती हैं और तेज़ी से इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाती हैं।

युवाओं को रोजगार देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: अग्रवाल

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और रोजगार देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने शनिवार को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन मुख्यालय, अलीगंज लखनऊ में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि योगी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का प्रत्येक युवा हुनरमंद बने, आत्मनिर्भर बने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता, समयबद्धता और उच्च गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों की वास्तविक समय आधारित निगरानी सुनिश्चित की जाए, प्रशिक्षकों की उपस्थिति और प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाए, जबकि कमजोर प्रदर्शन वाले संस्थानों से लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि उद्योगों की मांग और युवाओं की रुचि के अनुरूप नए व्यवसाय आरंभ किए जाएं और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार क्षेत्रों का उन्नयन किया जाए, ताकि युवाओं को उनके जनपद में ही बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें। बैठक में प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम, विशेष सचिव अभिषेक सिंह, निदेशक कौशल विकास मिशन पुलकित खरे, अपर मिशन निदेशक प्रिया सिंह, अपर निदेशक मानपाल सिंह, संयुक्त निदेशक मयंक गंगवार, राजेन्द्र प्रसाद सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध' कर उप्र को सशक्त बना रही योगी सरकार

- धान किसानों को किया गया 1868.35 करोड़ रुपये का भुगतान

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। योगी सरकार किसानों को आर्थिक रूप से 'समृद्ध' कर उत्तर प्रदेश को सशक्त बना रही है। सीएम योगी के निर्देश के उपरांत 48 घंटे के भीतर धान व बाजरा किसानों को किया जा रहा भुगतान इसका उदाहरण है। पहली अक्टूबर से धान खरीद शुरू हुई थी, तबसे 28 नवंबर तक धान किसानों को 1868.35 करोड़ व बाजरा किसानों को 263.03 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। यही कारण है कि योगी सरकार की पारदर्शी नीतियों की बदौलत अपनी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के लिए किसान फसल की बिक्री राजकीय क्रय केंद्रों पर कर रहे हैं। क्रय केंद्रों पर 17 फीसदी नमी तक का धान खरीदा जा रहा है।

धान किसानों को 1868.35 करोड़ रुपये का भुगतान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर समय-समय पर धान खरीदारी की समीक्षा हो रही है। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, खाद्य व रसद विभाग लगातार इसकी मॉनीटरिंग कर रहा है। पहली अक्टूबर से 28 नवंबर तक के मध्य सरकारी क्रय केंद्रों पर 1.40 लाख से अधिक किसानों ने धान बिक्री की। इसके एवज में किसानों को अब तक 1868.35 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। बचे किसानों के लिए भी सरकार द्वारा तत्काल भुगतान की प्रक्रिया चालू है।

बाजरा किसानों को 263.03 करोड़ का किया गया भुगतान यूपी में श्री अन्न की खरीद भी पहली अक्टूबर से जारी है। श्री अन्न के अंतर्गत बाजरा किसान भी सरकारी क्रय केंद्रों पर अपनी फसल को लेकर जा रहे हैं। 28 नवंबर तक लगभग 22000 किसानों को 263.03 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। शेष बचे किसानों को भी तत्काल भुगतान करने की प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है। बाजरा की बिक्री के लिए 64 हजार से अधिक किसानों ने पंजीकरण भी करा लिया है। 2775 रुपये प्रति कुंतल एमएसपी पर हो रही बाजरा की खरीद बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2775 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है। बाजरा खरीद सिर्फ 33 जनपदों में ही हो रही है। इसके लिए 281 क्रय केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। धान खरीद (कॉमन) 2369 रुपये तथा (ग्रेड-ए) 2389 रुपये प्रति कुंतल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर हो रही है।

वर्ल्ड पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के गुरु-शिष्य की जोड़ी ने लहराया जीत का परचम

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में आगरा जिले के इटौरा स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के व्यायाम शिक्षक हरीश चंद्र और कक्षा 11 के छात्र रमन कुमार ने शानदार प्रदर्शन किया है।

हरीश चंद्र ने 77 किग्रा भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर विश्व चैंपियन का खिताब हासिल किया, जबकि युवा छात्र रमन कुमार ने 56 किग्रा भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया।

वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में 40 से अधिक देशों के एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर, गुरु और शिष्य की जोड़ी ने देश को गौरान्वित किया। शिक्षक हरीश चंद्र ने 77 किग्रा भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर विश्व चैंपियन का खिताब हासिल किया। वहीं छात्र रमन कुमार ने 56 किग्रा भार वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता।

प्रदेश सरकार की खेल नीतियों के कारण दोनों खिलाड़ियों का चयन हाल ही में गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में उनके दमदार प्रदर्शन के आधार पर हुआ था। हरीश चंद्र ने सीनियर 77 किग्रा वर्ग में गोल्ड जीतने के साथ ही डेडलिफ्ट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया था, जबकि रमन कुमार ने सब-जूनियर 56 किग्रा वर्ग में गोल्ड जीता था।

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने इस उपलब्धि पर दोनों खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोलंबो में मिली यह ऐतिहासिक उपलब्धि पूरे प्रदेश और देश के लिए गर्व का विषय है। सर्वोदय विद्यालय इटौरा के छात्र और शिक्षक ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर जो प्रदर्शन किया है, वह आने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। योगी सरकार हमेशा खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सर्वोदय विद्यालय इटौरा लगातार खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने में अग्रणी रहा है। विभाग अब इस सफलता को आगे बढ़ाने के लिए सुविधाओं को और मजबूत कर रहा है। जिला समाज कल्याण अधिकारी घासीराम प्रजापति ने बताया कि जल्द ही विद्यालय में अत्याधुनिक पावर लिफ्टिंग लैब बनकर तैयार हो जाएगी। इसके लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा 10 लाख रुपए की धनराशि भी दी गई है। यह राशि लैब में पावर लिफ्टिंग के अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने

एसआईआर को लेकर जल्दबाजी क्यों, चुनाव आयोग और भाजपा मिले हुए हैं : अखिलेश

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। अखिलेश ने शनिवार को कहा कि एस आई आर को लेकर इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं।

श्री यादव ने पत्रकारों से कहा कि शादियों के मौसम में सभी लोग व्यस्त हैं। इसी समय आयोग एसआईआर करवा रहा है। आख़िर भाजपा और आयोग के बीच क्या सेटिंग है। एस आई आर को लेकर कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। अखिलेश ने कहा है कि प्रदेश में लगातार शादियां हो रही हैं और शादियों के समय पर लोगों का एक दूसरे के यहा आना-जाना, शादी की तैयारी करना सब व्यस्त हैं। इतने कम समय में एसआईआर कराना पूरे प्रदेश का और किस-किस को आपने जिम्मेदारी दी हैं।

अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एसआईआर कराने की जल्दी क्यों है। नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को सहायक बनाया गया है।

लखनऊ में शनिवार को अखिलेश यादव ने मलिहाबाद के मृतक बीएलओ विजय कुमार वर्मा की पत्नी और बेटे को 2 लाख रुपये का चेक सौंपा और कहा कि बीएलओ विजय कुमार की मौत ड्यूटी के दौरान ही हुई। अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह ड्यूटी पर ना दिखाएं।बहुत सारे बीएलओ को जानकारी नहीं है। बिना ट्रेनिंग की एसआईआर की प्रक्रिया का काम कराया जा रहा है।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में जल्द बढ़ेंगी ज़मीन अधिग्रहण दरें

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ज़मीन अधिग्रहण की दरों में वृद्धि के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यह फैसला किसानों की लगातार उठ रही उस मांग के बाद आया है, जिसमें उन्होंने वर्तमान दरों को बाज़ार मूल्य से काफी कम बताते हुए संशोधन की बात कही थी।

फिलहाल गौतमबुद्ध नगर में सरकार द्वारा तय दरें नोएडा में 5,100 रुपये प्रति वर्गमीटर, ग्रेटर नोएडा में 4,100 रुपये प्रति वर्गमीटर और यमुना सिटी में 4,300 रुपये प्रति वर्गमीटर हैं। लंबे समय से इन दरों में बदलाव न होने के कारण किसानों में असंतोष बढ़ रहा था।

सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, सरकार नोएडा में दरों को बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति वर्गमीटर और ग्रेटर नोएडा में 7,000 रुपये प्रति वर्गमीटर करने पर विचार कर रही है। वहीं यमुना सिटी की दरें वर्ष 2024 में ही संशोधित की गई थीं, इसलिए यहां तत्काल बढ़ोतरी की संभावना कम है।

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश गुरुवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के निरीक्षण के दौरान दिए थे। इस मौके पर उन्होंने ज़मीन अधिग्रहण से जुड़ी लंबित समस्याओं और किसानों के विरोध से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह ने निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के सामने सीधे यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने बताया कि किसानों की मांग को लेकर पहले भी राज्य सरकार और औद्योगिक विकास विभाग से वार्ता की गई थी।

उन्होंने कहा कि, ल्लगुरुवार को हवाईअड्डे के निरीक्षण के दौरान हमने पुनः इसे उठाया। हमारी बात पर मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार को दरें बढ़ाने का निर्देश दिया, ताकि किसानों को उचित लाभ मिल सके।

विद्यार्थियों को छात्र जीवन के पंचशील के सिद्धांत बताए

- अर्बन पब्लिक स्कूल में भाग्योदय फाउंडेशन की विद्यार्थी शिक्षक गोष्ठी
- अध्यापक हैं युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। चिनहट के जगपालखेड़ा गांव स्थित अर्बन पब्लिक स्कूल में आज भाग्योदय फाउंडेशन की विशेष गोष्ठी संपन्न हुई। विद्यालय परिसर में भारी संख्या में उपस्थित विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को बतौर मुख्य वक्ता भाग्योदय प्रमुख आचार्य राम महेश मिश्र ने संबोधित किया। इस अवसर पर भाग्योदय परिवार में संस्कृति एवं संस्कार प्रभाग के निदेशक आचार्य श्याम मोहन शर्मा, विद्यालय के प्रबंधक अरुण यादव, लोकसेवी मोहित नन्दन पाण्डेय, एस. के. यादव विशेष रूप से मौजूद रहे।

भाग्योदय फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं संस्थापक आचार्य राम महेश मिश्र ने विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पंचशील के सिद्धांत छात्र-छात्राओं को बताए और उनकी विस्तार से व्याख्या की। उन्होंने शालीनता, श्रमशीलता, सुव्यवस्था, मितव्ययिता और सहकारिता को जीवन में धारण करने की प्रेरणा विद्यार्थियों को दी। उन्होंने विद्यार्थी जीवन में आने वाली बाधाओं और उनके निदान पर प्रकाश डाला। किशोरावस्था को बहुत संवेदनशील बताते हुए श्री मिश्र ने उनसे कहा कि आप इस आयु को संभाल ले जाएं, आपका पूरा जीवन सुखमय रहेगा। उन्होंने प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों से कहा कि गुरु का पद इस धरती का सबसे बड़ा पद है। अभिभावक अपने बच्चों को आपकी गोद में बड़े विश्वास के साथ भेजते हैं, उनका आप बड़े अच्छे ढंग से निर्माण करें। उन्होंने शिक्षकों को युग निर्माता और विद्यार्थियों को राष्ट्र के भाग्य विधाता की संज्ञा दी। भाग्योदय फाउंडेशन के निदेशक (संस्कृति एवं संस्कार) आचार्य श्याम मोहन शर्मा ने वेद मंत्रोच्चार के बीच छात्र-छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना की और उन्हें राम और कृष्ण के बचपन के प्रसंग सुनाते हुए मर्यादित एवं सुसंस्कृत जीवन जीने को कहा। उन्होंने खेल-खेल में उन्हें उसके विविध सूत्र समझाए।

विद्यालय प्रबंधक अरुण यादव ने भाग्योदय फाउंडेशन के मुख्य वक्ताओं को धन्यवाद दिया तथा विद्यालय से निरंतर जुड़े रहने का अनुरोध किया। प्रधानाचार्य वंदना श्रीवास्तव ने भाग्योदय फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक ''समग्र व्यक्तित्व निर्माण एवं सफल जीवन के 108 महत्वपूर्ण सूत्र'' की प्रतियां सभी विद्यार्थियों में वितरित कराईं। प्रिंसिपल ने अभिभावकों को संदेश देते हुए कहा कि विद्यालय में दिए गए गुण-सूत्रों का पालन परिवार में कराएं। इसके पूर्व प्रत्येक कक्षा के एक-एक विद्यार्थी ने भाग्योदय प्रमुख आचार्य राम महेश मिश्र एवं अतिथियों को पुष्प भेंट करके उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर सरस्वती वंदना भी की गई।

विधायक ने 155 सहायक उपकरण दिव्यांगजनों को वितरित किए

राष्ट्रीय प्रस्तावना

हरदोई। विकास खंड बिलग्राम में विधायक आशीष सिंह आशू एवं ब्लाक प्रमुख सत्येंद्र सिह मुन्ना के कर कमलो द्वारा दिव्यांगजन बंधुओ को ट्राई साइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, स्मार्ट केन आदि 155 सहायक उपकरण दिव्यांगजनों को वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनकी समस्याओं को निस्तारित करने के निर्देश दिए गए।

कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी शाहाबाद, एवं जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी हरदोई आदि उपस्थित रहे।

01 दिसम्बर 2025 तक अपनी आपत्ति लिखित रुप में दर्ज करा सकते है: रामाकान्त

हरदोई (राष्ट्रीय प्रस्तावना)। जिला समाज कल्याण अधिकारी रामाकांत ने सूचित किया है कि राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास मन्नापुरवा एवं राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास जी0आई0सी0 परिसर हरदोई में छात्रों के शैक्षिक सत्र 2025-26 में नवीन प्रवेश हेतु आनलाईन आवेदन किये गये थे छात्रावासों के सफल संचालन हेतु शासनादेश में बिन्दु संख्या 02 में दी गई व्यवस्था के अनुसार छात्रावास में प्रवेश हेतु कुल उपलब्ध क्षमता का 70 प्रतिशत् स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति अभ्यार्थियों के लिये होगें तथा अवशेष 30 प्रतिशत् अन्य पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग की छात्रों के प्रवेश हेतु प्राथमिकता का आधार आर्थिक होगा। तदानुसार छात्रावास में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये 70 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत् सामान्य व पिछड़े वर्ग के आरक्षित अभ्यर्थियों के प्रवेश चयन हेतु प्रक्रिया प्रचलित है अतएव प्रवेश हेतु नवीन प्राप्त आवेदन के अनुसार चयनित किये गये छात्रों की सूची छात्रावास में चश्पा है, के दृष्टिगत उक्त छात्रावासों में आवेदन करने वाले प्रवेश हेतु यदि किसी छात्र की कोई आपत्ति हो तो (03 दिवस) में 01 दिसम्बर 2025 तक अपनी आपत्ति लिखित रुप में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दर्ज करा सकते है।

आधार नामांकन केन्द्र कई महीनों से बंद, जनता परेशान

कछौना (हरदोई)(राष्ट्रीय प्रस्तावना)। वर्तमान समय में ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) कछौना में आधार कार्ड नामांकन केन्द्र पर कार्य प्रभावित होने के कारण नाम संशोधन, मोबाइल नंबर लगवाने वालेए नया आधार कार्ड बनवाने वाले दर-दर भटकने को विवश है। पूरे मामले की जानकारी जन सरोकार मंच ने क्षेत्रीय विधायक रामपाल वर्मा को अवगत कराई, उन्होंने जिला अधिकारी को पत्र लिखकर आधार कार्ड नामांकन केन्द्र को सुचारू रूप से चालू कराने के लिए अवगत कराया। वर्तमान समय में लगातार आधार कार्ड की उपयोगिता काफी बढ़ गई है। बिना आधार कार्ड के विद्यालय में प्रवेशए सरकारी योजनाओं का लाभ से वंचित होना पड़ता है। लोग कस्बा सहित दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में से नया आधार कार्ड बनवाने हेतुए नाम संशोधन, बायोमेट्रिक, मोबाइल नंबर लगवाने हेतु सुबह से केन्द्रो के चक्कर लगाने लगते हैं। परंतु कछौना कस्बा में ब्लॉक संसाधन केंद्र कछौना में आधार कार्ड की सुविधा लगभग एक वर्ष से प्रभावित है। कछौना विकासखंड की लगभग दो लाख की आबादी प्रभावित है। सुविधा का लाभ न मिल पाने के कारण लोगों के आवश्यक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा नोनीहालों छात्रों को समस्या हो रही है। उनकी नामांकन प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। विभिन्न योजनाओं में आधार कार्ड की अनिवार्यता होने के कारण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मेरा आधार मेरी पहचान स्लोगन लोगों को चिढ़ा रहा है। जन सरोकार मंच के परमेश्वर दयाल, अंकित कुमार, क्षेत्रीय विकास जन आंदोलन के अध्यक्ष रामखेलावन कनौजिया सहित लोगों ने पूरे मामले की शिकायत क्षेत्रीय विधायक रामपाल वर्मा से की। विधायक रामपाल वर्मा ने जिला अधिकारी को तत्काल आधार कार्ड नामांकन केंद्र सुचारू रूप से चालू करने के लिए पत्र लिखकर अवगत कराया है।

अधिकारी/कर्मचारी बिना जिलाधिकारी की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगें: प्रफुल्ल त्रिपाठी

हरदोई (राष्ट्रीय प्रस्तावना)। अपर मजिस्ट्रेट न्यायिक/उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी ने भारत निर्वाचन आयोग, के निर्देशन के क्रम में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दृष्टि गत इस प्रक्रिया में लगे जनपद के समसत अधिकारी/कर्मचारी को निर्देश दिये है कि वे बिना जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगें और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

13 दिवसीय नि:शुल्क प्रशिक्षण के लिए आवदेन करें:- विक्रांत ओझा

हरदोई (राष्ट्रीय प्रस्तावना)। निदेशक आरसेटी विक्रांत ओझा ने बताया है कि बैंक ऑफइंडिया ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जनपद के 18 वर्ष से 50 वर्ष तक के बेरोजगार युवक/युवतियों के स्वरोजगार स्थापना हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरा,सिक्योरिटी आलर्म और स्मोक डिटेक्टर/फायर अलार्म इन्सटालेशन और सर्विसिंग का 13 दिवसीय नि:शुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम 29 नवम्बर से प्रारंभ होना प्रस्तावित है। प्रशिक्षण के दौरान नास्ते, भोजन और आवास की सुविधा पूर्णतया नि:शुल्क उपलब्ध है। प्रशिक्षण के साथ प्रशिक्षणार्थियों को मार्केट सर्वे,बिजनेस प्लान,उद्यमिता विकास,प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा बैंकिंग की जानकारी भी प्रदान की जाती है साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अन्तर्गत लोन फॉर्म आवेदन की भी सुविधा। इच्छुक अभ्यर्थी शीघ्र संपर्क करें,सीट सीमित है। उन्होने कहा है कि रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ है तथा आवेदन पत्र के आधार कार्ड, न्यूनतम 5वीं पास प्रमाण पत्र, स्वयं सहायता समूह/राशन कार्ड/मनरेगा कार्ड/की फोटो कापी तथा 4 रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न कर राजकीय पालीटेक्निक,बावन रोड, तत्योरा हरदोई कार्यालय में जमा करें अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नम्ब-7379969627, 9140650306, 8127520102,7572064711,9044801001 पर सम्पर्क करें।

जर्ज़र मार्ग के निर्माण की ग्रामीणों ने की मांग

कछौना (हरदोई)(राष्ट्रीय प्रस्तावना)। विकासखंड कछौना के ग्राम तेरवा से कछौना व गोठवा मार्ग को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग लगभग एक दशक से अपेक्षित पड़ा है! जिससे ग्रामीणों को आवागमन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है! इस मार्ग के जीर्णोद्धार के लिए ग्रामीण शासन से लगातार मांग कर रहे हैं! बताते चलें विकास खंड कछौना का कछौना से गोठवा संपर्क मार्ग को जोड़ने वाला मार्ग मंडी समिति के अंतर्गत आता है जिसकी दूरी लगभग एक किलोमीटर है! लगभग एक दशक से अपेक्षित यह मार्ग पूरी

तरीके से क्षतिग्रस्त है! मार्ग में गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं! इस मार्ग से कछौना से तेरवा देवनपुर तुसौरा, शंकर खेड़ा, झरिहाई रुदनखेड़ा, सरसंड, अरसेनी आदि दर्जनों गांव के ग्रामीणों का प्रतिदिन आवागमन रहता है! इस दिशा में बालामऊ जंक्शन, प्रमुख बाजार, अस्पताल, विद्यालय होने के कारण सैकड़ो लोगों का प्रतिदिन आवागमन रहता है! कई बार वाहन पलटने से दुर्घटनाएं घट चुकी हैं! सड़क की हालत काफी बदहाल है आए दिन नैनीताल इन गड्ढों में गिरकर चुटहिल होते रहते हैं! सबसे ज्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं, मरीजों व नैनिहालों को उठानी पड़ती है! इस मार्ग से निकलना जान को जोखिम डालने से कम नहीं है! ग्रामीणों के लगातार कई वर्षों से मांग के बावजूद सड़क के निर्माण की कोई सुध नहीं ले रहा है! जिसका खामियाजा आमजन को उठाना पड़ रहा है!

प्रोफेसर मेडिकल कालेज लखनऊ ने किया राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय का औचक निरीक्षण

राष्ट्रीय प्रस्तावना

कोथावाँ (हरदोई)। प्रोफेसर डीके सोनकर सीनियर प्रोफेसर लखनऊ होम्योपैथिक मेडिकल कालेज ने राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय कल्यानमल हरदोई का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान प्रोफेसर ने बारीकी से कई बिंदुओं पर जांच की व समय पर सभी को ड्यूटी पहुंचने के सक्त निर्देश दिए। साफ-सफाई की व्यवस्था को लेकर भी कड़े निर्देश दिए व अलग-अलग कई मरीजों से भी बात की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डा ममता शर्मा को निर्देशित किया कि मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न होने पाऐ शासन से लगातार दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है मौके पर मिली प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ ममता शर्मा व फार्मासिस्ट अखिलेश वर्मा, कमल कामले, शिवदीप सिंह व योगा टीचर हरि कृष्ण शुक्ला, मंदाकिनी शुक्ला व कई ग्राम वासी मौके पर मौजूद रहे टिंकू दीक्षित रामविलास पाल, चौधरी द्विवेदी, कार्तिक द्विवेदी, व सुनैना श्रीवास्तव व कई अन्य लोग मौके पर उपस्थित रहे।

सरकार का करोड़ों रूपए का बजट लेकिन ग्राम पंचायत भदेउरा में जल जीवन मिशन अधूरा

राष्ट्रीय प्रस्तावना

हरियावाँ (हरदोई)। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल योजना के तहत करोड़ रुपए खर्च किए हैं लेकिन जल जीवन मिशन अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है हकीकत कुछ और ही है कहीं सड़के खोद कर डाल दी गयी है जिससे लोगों का निकलना दुसबार हो रहा है तो कहीं पाइप डाल दी गई है अभी तक सप्लाई जोड़ी नहीं गई है आपको बता दे पूरा मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद के विकासखंड हरियावां के भदेउरा ग्राम पंचायत का है जहां ठेकेदारों की लापरवाही उजागर हुई है।

आपको बताते चलें ग्राम पंचायत भदेउरा में पड़ोस की ही ग्राम पंचायत अलावलपुर के मजरा गाड़ीपुरवा में स्थित पानी टँकी से जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन डालकर पानी की सप्लाई जोड़ी गई है लेकिन हकीकत कुछ और ही है ठेकेदारों व जल जीवन मिशन के इंजीनियरों की लापरवाही उजागर हुई है ग्राम पंचायत में पाइप तो पड़ गई है लेकिन पानी सप्लाई के लिए ना ही कनेक्शन जोड़ा गया है नहीं लोगों के कनेक्शन किये गए हैं और सड़कों पर खोदे गए गड्ढे बने हुए हैं जिनमें कई बार लोग गिर कर चोटहिल भी हो जाते हैं लेकिन अभी भी कई वर्षों से हो रहा जल जीवन मिशन का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है जहां ठेकेदारों और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई है सरकार के करोड़ों खर्च करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं और सरकार के दिए गए निर्देश पर खरा नहीं उतर रहे हैं जबकि सरकार द्वारा कई बार हर घर जल योजना के तहत समीक्षा भी की जाती है लेकिन जिम्मेदार अपनी लापरवाही उजागर करने से बाज नहीं आ रहे हैं।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीड़न के संबंध में शी-बाक्स पोर्टल संचालित: डीएम

राष्ट्रीय प्रस्तावना

■ समस्त शासकीय एवं निजी कंपनियों, फर्मो, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नामित नोडल अधिकारियों का पोर्टल पर पंजीकरण कराया जायेगा: अनुनय झा

हरदोई। जिलाधिकारी अनुनय झा ने अवगत कराया है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा शी-बाक्स पोर्टल संचालित किया गया है जो उकत अधिनियम से सम्बन्धित सूचनाओं एवं प्राप्त शिकायतों की मॉनीटरिंग की दृष्टि से केन्द्रीय भण्डार के रूप में कार्य करेगा।

डीएम ने बताया कि शी-बाक्स पोर्टल इस प्रकार बनाया गया है कि ऐसे कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 10 या 10 से अधिक हो कार्यालायों/विभागों में गठित आंतरिक समितियों के कार्य विवरण पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जायेगा तो उस विभाग/कार्यालय के कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न सम्बन्धित कोई भी शिकायत पोर्टल के माध्यम से दर्ज कराया जाना सम्भवन नहीं होगा। उन्होने कहा है कि जनपद में डिस्ट्रिक नोडल ऑफिसर (जिला प्रोबेशन अधिकारी) द्वारा जनपद, ब्लाक व तहसील स्तर पर अवस्थित समस्त शासकीय एवं निजी कंपनियों, फर्मो, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नामित नोडल अधिकारियों का पोर्टल पर पंजीकरण कराया जायेगा। डीएम ने समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश देते हुए कहा है कि जहां कार्मिकों की सख्या 10 या 10 से अधिक है, वह अपने कार्यालय से सम्बन्धित विवरण निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं ई0मेल आईडी पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे शी- बाक्स पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुए आईडी बनवायी जा सके। उन्होने कहा है कि पंजीकरण के पश्चात संबंधित कार्यालय/विभाग द्वारा उनकी मेल ई-मेल आईडी पर प्राप्त स्वत/जनेरेटेड आईडी व पासवार्ड द्वारा पोर्टल पर लॉगिन करते हुए आन्तरिक परिवाद के सदस्यों का विवरण अपोड किया जायेगा।

सीडीओ ने आवेदन पत्रों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा बैठक की

राष्ट्रीय प्रस्तावना

हरदोई। मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा द्वारा 28 नवम्बर, 2025 को विकास भवन, सभागार, हरदोई में पूर्वाह्न 11:00 बजे दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11-12 को छोड़कर अन्य दशमोत्तर कक्षाएं) योजनान्तर्गत छात्रों द्वारा ऑनलाइन किये गये आवेदन पत्रों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा बैठक की गयी।

उक्त बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हरदोई, प्राचार्य, महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय/नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति योजना), हरदोई तथा सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारियों/प्राचार्य/प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिभाग किया गया। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा छात्रों द्वारा आवेदन पत्रों के सापेक्ष शिक्षण संस्थान द्वारा एक भी आवेदन पत्र ऑनलाइन अग्रसारित न किये जाने की समीक्षा की गयी तथा ऑनलाइन अग्रसारित करने हेतु लम्बित आवेदन पत्रों पर असन्तोष व्यक्त किया गया। साथ ही शिक्षण संस्थान स्तर पर ऑनलाइन अग्रसारण हेतु लम्बित आवेदन पत्रों को समयान्तर्गत शत-प्रतिशत आवदेन पत्रों को अग्रसारित करने की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही पोर्टल संचालन की गति धीमी होने की दशा में कार्य दिवस के उपरान्त भी अग्रसारण की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अनुपस्थित रहे नोडल अधिकारियों/प्राचार्य/प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। लम्बित आवेदन पत्रों को ससमय अग्रसारित न करने की दशा में सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये।

हरदोई को बाल विवाह मुक्त जनपद बनाना हम सब का लक्ष्य होना चाहिए: संतोष

राष्ट्रीय प्रस्तावना

हरदोई। जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार निगम ने बताया है कि बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग एवं पेस संस्था के संयुक्त तत्वावधान में बाल विवाह निषेध जागरुकता अभियान के अंतर्गत प्रथम चरण में ग्रामोदय इंटर कॉलेज डिघिया-खेरिया हरदोई की छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली जिसमें हमको प्यार दुलार चाहिए! शिक्षा का अधिकार चाहिए!! जैसे गगनभेदी नारों से वातावरण गुंजायमान रहा। महिला कल्याण विभाग की ओर से प्रचार सामग्री वितरित की गई। द्वितीय चरण में विद्यालय की बालिकाओं और उनके अभिवावकों के साथ संवाद सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। संवाद सभा की अध्यक्षता न्यायपीठ बाल कल्याण समिति हरदोई के अध्यक्ष सन्तोष कुमार सिंह ने की और संयोजन पेस संस्था के जिला क्वार्डिनेटर अवनीश मिश्र ने किया। संवाद के दौरान न्यायपीठ के अध्यक्ष सन्तोष कुमार सिंह के कहा कि राष्ट्रीय आंकड़े की तुलना में हमारा जनपद बेहतर स्थिति में है किंतु हम इतने से संतुष्ट हो कर बच्चों के बचपन हत्या होते देखना नहीं चाहते। हरदोई को बाल विवाह मुक्त जनपद बनाना हम सब का लक्ष्य होना चाहिए। इस अवसर पर छात्राओं ने दीप प्रज्वलित कर 100 दिन के बाल विवाह निषेध जागरुकता अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया और आगामी 100 दिन के कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए पेस संस्था की सचिव राजविंदर कौर ने उपस्थित सभी को हाथ उठा कर बाल विवाह न करने और न होने देने तथा इसकी प्रशासन को समय से सूचना देने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के तृतीय चरण में छात्र-छात्राओं ने मिलकर कैंडल लाइट से जगह-जगह बाल विवाह रोकों के चित्र उकेरे।

कार्यक्रम में बाल संरक्षण इकाई हरदोई के सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार राही, चाइल्ड हेल्पलाइन हरदोई के समन्वयक अनूप तिवारी सहित अनेक बुद्धिजीवी, समाजसेवी और अधिवक्ता उपस्थित रहे।

लोनी चीनी मिल के खोई लदे हुए ओवरलोडेड ट्रक बने हैं दुर्घटनाओं का सबब, पुलिस नहीं दे रही ध्यान

राष्ट्रीय प्रस्तावना

शाहाबाद (हरदोई)। नगर क्षेत्र में चीनी मिल के खोई लदे हुए ओवरलोडेड ट्रक हादसों को आमंत्रण दे रहे हैं। कोतवाली और बस स्टैंड स्थित पुलिस चौकी के सामने से यह ओवरलोडेड ट्रक धड़ल्ले के साथ गुजर रहे हैं। न पुलिस को दिख रहा है और न टीआई को दिख रहा है। हमारे दर्शक यह वीडियो जो देख रहे हैं यह सोमवार को शाम 05:00 बजे का है। दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह से ओवरलोडेड ट्रक बस स्टैंड चौराहे से गुजर रहा है। किसी भी समय यह ट्रक दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। यह सभी ट्रक लोनी चीनी मिल द्वारा खोई लाद कर भेजे जा रहे हैं।

बीएलओ की आत्महत्या चिंताजनक

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर विवाद खत्म होने की जगह अब घातक होता जा रहा है। एसआईआर पर विपक्ष की आपत्ति को कुछ पल के लिए अलग रखें तो भी इस समूची प्रक्रिया में पूरे देश में अब तक 25 बीएलओ की मौतें सचमुच चिंता पैदा करने वाली हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक 34 मौतें हो चुकी हैं। अब आंकड़ें जो भी हों, अगर एक भी बीएलओ की मौत इस वजह से होती है कि उस पर एसआईआर करवाने का दबाव था या चुनिंदा लोगों के नाम काटने के लिए उसे धमकाया जा रहा था, तो यह एसआईआर की प्रक्रियागत खामी की ओर इशारा करती है। जिस पर तत्काल संज्ञान लेने की जरूरत है।गुजरात, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश इन तमाम राज्यों में भाजपा सरकारें हैं जो पूरी तरह से एसआईआर के समर्थन में है, क्या इन राज्य सरकारों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उनके राज्य में इस तरह अकाल मौतें हो रही हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस सभी दल ऐसी मौतों पर अब चिंता जता रहे हैं। अभी गोंडा में ही एक मामला सामने आया है, जिसमें अपनी शादी से एक दिन पहले बीएलओ विपिन यादव ने आत्महत्या कर ली। विपिन यादव के परिवार का कहना है कि एसडीएम और लेखपाल एसआईआर में ओबीसी वोटरों के नाम काटने का दबाव बना रहे थे। विपिन यादव ने ऐसा करने से मना किया तो उन्हें नौकरी से निकालने और पुलिस से उठवाने की धमकी दी गई।परिवार का आरोप है कि विपिन यादव से कहा गया था कि ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी खत्म कर दी जाएगी। जिसके बाद विपिन यादव ने आत्महत्या कर ली। यह मामूली आरोप नहीं है और इसकी गहन जांच की जरूरत है। कांग्रेस ने इस पर लिखा भी है कि ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को खत्म करने पर तुले हैं और एसआईआर उसी का औजार है।वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लिखा है कि एसआईआर वोटरों के नाम काटो, वरना नौकरी चली जाएगी।ये दबाव, धमकी और नतीजा? आखिर में आत्महत्या। एसआईआर के नाम पर पिछड़े-दलित-वंचित-गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर भाजपा अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या की जिम्मेदार है।ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग पर इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं और उसे भाजपा के पक्ष में काम करने के लिए घेरा है। जिस पर भाजपा नेताओं ने कहा है कि ममता बनर्जी अपनी हार के बहाने बता रही हैं। इसी तरह अखिलेश यादव भी बीएलओ की मौतों पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि किस तरह इंडिया गठबंधन की जीती हुई सीटों पर वोट काटने की तैयारी हो रही है, तो भाजपा उनकी भी आलोचना कर रही है। यह प्रवृत्ति स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। विपक्ष के पास अभी कम राज्य हैं, या भाजपा की तुलना में उसका जनाधार कम है, तो इससे उसका राजनैतिक महत्व कम नहीं हो जाता। याद रहे कि लोकसभा में भाजपा खुद के बूते बहुमत हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि विपक्ष उस पर भारी पड़ गया। अगर विपक्षी नेता किसी मुद्दे पर ध्यान दिला रहे हैं तो सरकार का काम है कि उसे पूरी ईमानदारी से सुने। सरकार की तरह चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है कि वह अपनी निष्पक्षता का यकीन सारे दलों को दिला पाए। फिलहाल लगता है कि चुनाव आयोग को विपक्ष के संदेहों से कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यायपालिका से भी यही अपेक्षित है कि वह बीएलओ की अकाल मौतों का स्वतः संज्ञान ले। अभी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच एसआईआर की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। बुधवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, श्आधार कार्ड एक कानून की रचना है। और वैध है। इस हद तक कि यह उस पर आधारित लाभों या विशेषाधिकारों को स्वीकार करता है। कोई भी इस पर विवाद नहीं कर सकता। लेकिन क्या आधार को मतदान के अधिकार से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या आधार रखने वाले घुसपैठियों को वोटिंग के अधिकार देना चाहिए। वैसे मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयोग से पहले यह पूछना चाहिए था कि बिहार में उसे कितने घुसपैठिए मिले, उनके नाम वह बताएं। इसी तरह उन्हें बीएलओ की मौत पर भी सवाल करने चाहिए थे। क्योंकि 2003 में जो देशव्यापी एसआईआर हुआ था, वह प्रक्रिया 6 माह में पूरी हुई थी। तब न तो कहीं विरोध

एसआईआर पर विपक्ष की आपत्ति को कुछ पल के लिए अलग रखें तो भी इस समूची प्रक्रिया में पूरे देश में अब तक 25 बीएलओ की मौतें सचमुच चिंता पैदा करने वाली हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक 34 मौतें हो चुकी हैं। अब आंकड़ें जो भी हों, अगर एक भी बीएलओ की मौत इस वजह से होती है कि उस पर एसआईआर करवाने का दबाव था या चुनिंदा लोगों के नाम काटने के लिए उसे धमकाया जा रहा था, तो यह एसआईआर की प्रक्रियागत खामी की ओर इशारा करती है। जिस पर तत्काल संज्ञान लेने की जरूरत है।गुजरात, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश इन तमाम राज्यों में भाजपा सरकारें हैं जो पूरी तरह से एसआईआर के समर्थन में है, क्या इन राज्य सरकारों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उनके राज्य में इस तरह अकाल मौतें हो रही हैं।

बदलती विश्व-व्यवस्था और जी-20 की चुनौती

डॉ. प्रियंका सौरभ

विश्व-राजनीति वर्तमान समय में गहरे परिवर्तनों से गुजर रही है। महाशक्तियों के बीच अविश्वास, क्षेत्रीय युद्ध, आर्थिक संकट, तकनीकी वर्चस्व की होड़, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे और वैश्विक संस्थाओं में घटती प्रभावशीलता ने विश्व-व्यवस्था को अस्थिर बना दिया है। ऐसे दौर में जी-20, जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने का सबसे महत्त्वपूर्ण मंच है, स्वयं को अभूतपूर्व चुनौतियों के बीच पाता है। समूह की प्रभावशीलता पर बढ़ते संदेह मात्र इसके कार्य-तंत्र से उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि यह बदलती विश्व-स्थिति और बहुध्रुवीयता के असंतुलन का प्रत्यक्ष परिणाम है।

जी-20 की सबसे गंभीर चुनौती गहराता हुआ भू-राजनीतिक विभाजन है। यूक्रेन क्षेत्र में चल रहा युद्ध, पश्चिम एशिया की अस्थिरता, प्रशांत क्षेत्र में टकराव, बड़े देशों के बीच तकनीकी एवं आर्थिक प्रतिस्पर्धा तथा बढ़ते प्रतिबंधों ने समूह की सहमति-निर्माण क्षमता को कमजोर बनाया है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि साझा घोषणा-पत्र निकालना भी कठिन हो जाता है। उदाहरणस्वरूप, जोहान्सबर्ग बैठक में केवल अत्यंत सामान्य रूप से 'स्थायी एवं न्यायपूर्ण शांति' की अपील की गई, क्योंकि सदस्य देशों के दृष्टिकोण आपस में टकराते रहे। यह स्थिति दिखाती है कि वैश्विक मुद्दों पर सामूहिक स्वर तैयार करना कितना कठिन हो चुका है। महाशक्तियों के व्यक्तिगत हित कई बार समूह के साझा हितों पर भारी पड़ जाते हैं। इससे ''उबंटू''-अर्थात मैं हूँ क्योंकि हम हैं-जैसी साझा जिम्मेदारी की मूल भावना क्षीण होती जा रही है। कुछ प्रमुख देशों द्वारा सम्मेलन से दूरी बनाना या महत्वपूर्ण विमर्शों में भागीदारी में अनिच्छा दिखाना, समूह की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। इससे जी-20 उस भूमिका को नहीं निभा पाता जिसके लिए यह बनाया गया था- यानी वैश्विक समस्याओं के समाधान हेतु सामूहिक एवं समन्वित प्रयास। इसके साथ ही आर्थिक असमानता जी-20 के सामने एक और महत्वपूर्ण चुनौती है। विकसित और विकासशील देशों के बीच आय, तकनीक, स्वास्थ्य-सुविधाएँ, कौशल, ऊर्जा स्त्रोतों और जलवायु वित्त में बढ़ती खाई ने समूह के भीतर संतुलन को प्रभावित किया है। वैश्विक ऋण संकट, विकासशील देशों पर बढ़ता आर्थिक दबाव, मंदी का खतरा और असमान व्यापार-संरचना मिलकर ऐसे परिदृश्य का निर्माण करते हैं जिसमें साझा नीति बनाना कठिन हो जाता है। ऐसे समय में समूह को जिस सशक्त नेतृत्व और सहयोग की आवश्यकता है, वह कई बार अनुपस्थित दिखाई देता है। इन जटिल परिस्थितियों के बीच भारत ने जी-20 में अत्यंत सकारात्मक, समावेशी और संतुलनकारी भूमिका निभाई है। भारत ने न केवल वैश्विक दक्षिण की चिंता और अपेक्षाओं को केंद्र में रखा बल्कि ऐसे ठोस कदम भी उठाए जिनका दीर्घकालिक प्रभाव दिखाई देता है। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि अफ्रीकी संघ को जी-20 की स्थायी सदस्यता दिलाना रही। यह निर्णय न केवल ऐतिहासिक था बल्कि उन विकासशील देशों की पुरानी मांग को भी पूरा करता था जिन्हें वैश्विक निर्णय-प्रक्रिया में बराबरी का स्थान नहीं मिलता रहा। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भारत वैश्विक व्यवस्था को अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने विकासशील देशों की वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित कई व्यावहारिक एवं मापनीय पहलों को आगे बढ़ाया। डिजिटल सार्वजनिक संरचना का मॉडल, स्वास्थ्य-सुरक्षा व्यवस्था, कौशल विकास, ग्रामीण एवं कृषि नवाचार, मत्स्य प्रबंधन, पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण, आपदा प्रबंधन में सहयोग और उपग्रह आँकड़ों का साझा उपयोग- ये सभी पहलें विकासशील देशों की आवश्यकताओं से सीधे जुड़ी हैं। विशेषकर ''अफ्रीका कौशल वृद्धि योजना'' जैसी पहलें लाखों युवाओं के लिए अवसरों का मार्ग खोलती हैं। भारत ने वैश्विक सुरक्षा से जुड़े महत्त्वपूर्ण मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया, विशेषकर आतंकवाद और नशीली दवाओं के गठजोड़ को। यह विषय लंबे समय से वैश्विक विमर्श में अपेक्षित महत्व नहीं पाता रहा था। भारत ने इसके विरुद्ध कठोर और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इसके साथ ही न्यायपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन, जलवायु वित्त, सतत विकास, तकनीक की समान उपलब्धता और खाद्य-सुरक्षा जैसे विषयों पर भी भारत ने विकासशील देशों की सामूहिक आवाज़ को मजबूत किया। हालाँकि भारत की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली रही है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएँ स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। महाशक्तियों के बीच चल रहे तीव्र संघर्षों के बीच भारत सभी पक्षों को एकजुट नहीं कर सका। प्रमुख देशों की अनुपस्थिति को भारत रोक नहीं पाया, न ही यह सुनिश्चित कर सका कि सभी देश साझा घोषणा-पत्र में कठोर रुख अपनाएँ। आतंकवाद पर अपेक्षित कठोर निंदा का शामिल न हो पाना भारत के लिए निराशाजनक था। इसी प्रकार भारत की कई विकास सम्बन्धी पहलें सभी देशों की समान रुचि और समर्थन प्राप्त नहीं कर पाईं, क्योंकि प्रत्येक देश की प्राथमिकताएँ भिन्न होती हैं। वैश्विक दक्षिण के भीतर भी कई बार मतभेद देखने को मिलते हैं, जिससे समग्र एजेंडा कमजोर पड़ता है। भारत की कूटनीति संतुलनकारी अवश्य है, परन्तु महाशक्तियों के कठोर और प्रतिस्पर्धी रुख के बीच इसकी प्रभाव सीमा सीमित हो जाती है। फिर भी यह निर्विवाद है कि आज वैश्विक दक्षिण का ऐसा कोई और देश नहीं है जो भारत जैसी व्यापक, संतुलित, विश्वासयोग्य और दूरदर्शी भूमिका निभा सके। भारत ने जी-20 के मंच को नई ऊर्जा दी है, वैश्विक दक्षिण के हितों को उचित सम्मान दिलाया है और वैश्विक शासन में समावेशिता की नई परिभाषा प्रस्तुत की है। अंततः, जी-20 की भविष्य की सफलता उसके सदस्यों की सामूहिकता की भावना, परस्पर विश्वास, और साझा उत्तरदायित्व को पुनर्जीवित करने पर निर्भर करेगी। यदि समूह ''उबंटू''-यानी साझा मानवता और साझा दायित्व- के सिद्धांत को पुनः अपनाता है, तो यह वैश्विक चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपट सकता है। भारत ने इस दिशा में मजबूत नींव रखी है और आने वाले समय में उसकी भूमिका और अधिक निर्णायक रूप से उभर सकती है।

जी-20 की सबसे गंभीर चुनौती गहराता हुआ भू-राजनीतिक विभाजन है। यूक्रेन क्षेत्र में चल रहा युद्ध, पश्चिम एशिया की अस्थिरता, प्रशांत क्षेत्र में टकराव, बड़े देशों के बीच तकनीकी एवं आर्थिक प्रतिस्पर्धा तथा बढ़ते प्रतिबंधों ने समूह की सहमति-निर्माण क्षमता को कमजोर बनाया है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि साझा घोषणा-पत्र निकालना भी कठिन हो जाता है। उदाहरणस्वरूप, जोहान्सबर्ग बैठक में केवल अत्यंत सामान्य रूप से 'स्थायी एवं न्यायपूर्ण शांति' की अपील की गई, क्योंकि सदस्य देशों के दृष्टिकोण आपस में टकराते रहे। यह स्थिति दिखाती है कि वैश्विक मुद्दों पर सामूहिक स्वर तैयार करना कितना कठिन हो चुका है। महाशक्तियों के व्यक्तिगत हित कई बार समूह के साझा हितों पर भारी पड़ जाते हैं। इससे ''उबंटू''-अर्थात मैं हूँ क्योंकि हम हैं-जैसी साझा जिम्मेदारी की मूल भावना क्षीण होती जा रही है। कुछ प्रमुख देशों द्वारा सम्मेलन से दूरी बनाना या महत्वपूर्ण विमर्शों में भागीदारी में अनिच्छा दिखाना, समूह की विश्वसनीयता को कमजोर करता है।

वंदे मातरम् है भारत की साकार अंतश्चेतना

गिरीश्वर मिश्र

वैश्विक स्तर पर भारत सदियों से अनेक देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा है । यह तथ्य अनेक साक्ष्यों से बहुशः प्रमाणित है कि प्राचीन भारत की भौतिक समृद्धि से प्रभावित हो खिंचे आए विदेशी आक्रान्ताओं ने भारत का अनेक प्रकार से शोषण और दोहन किया और अनैतिक ढंग से विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न अवधि के लिए अपना अनधिकृत आधिपत्य जमाया। इस प्रक्रिया में भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य और जीवन पद्धति में अनेक परिवर्तन आए। इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी के रूप में बर्तानवी (अंग्रेजी) उपनिवेश की लगभग दो सौ वर्षों की त्रासदी थी। यह इस अर्थ में विशेष अर्थ रखती है कि इस दौर में देश को न केवल भौतिक और आर्थिक क्षति पहुँची अपितु दुर्भाव के साथ उसमें मानसिक रूप से भी बदलाव भी लाया गया । शिक्षा के क्षेत्र में जो हस्तक्षेप किया गया उसके बड़े दूरगामी परिणाम हुए जिनसे हम आज तक नहीं उबर सके हैं। इस हस्तक्षेप के अंतर्गत भारतीय चिंतन , ज्ञान-परम्परा और भारतीय विश्व दृष्टि को अप्रासंगिक ठहरा कर उसे हाशिये पर डाल दिया गया। भारतीय प्रतिभा , कौशल और ज्ञान संपदा का समूचा अवदान कालबाह्य घोषित कर दिया गया। इस अहैतुक उपेक्षा का सीधा परिणाम यह हुआ कि हमारा आत्मबोध और हमारी पहचान पश्चिम के आलोक में परिभाषित की जाने लगी। पश्चिमी चिंतन वैज्ञानिक और आधुनिक कहलाते हुए मुख्यधारा बनकर हम सब पर थोप दिया गया। दूसरी तरफ़ भारतीय दृष्टि उस मुख्यधारा से विचलन के रूप में अग्राह्य और व्यर्थ मानी जाने जाने लगी। उसकी ओर सतत उपेक्षा और वितृष्णा की प्रवृत्ति ने एक ऐसा माहौल बनाया जो हमें सोच-विचार और अपनी निर्णय- क्षमता के लिए पर निर्भर कर दिया। हमने आचार-व्यवहार के लिए मानक भी उधार लेने शुरू कर दिए। हीनता और अपर्याप्तता की तीव्र अनुभूति से ग्रस्त हो कर बहुतों ने भारतीयता की अवधारणा को प्रश्नांकित कर डाला । फलतः भारत की मौलिक अस्मिता संशयग्रस्त बनने के लिए अभिशप्त हो गई, इतनी कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो नामकरण का निश्चय करते समय हमने भारत शब्द को अपर्याप्त मान लिया। अंततः भारतवर्ष के लिए इंडिया दैट इज भारत का नाम संविधान में दर्ज किया गया। घटनाक्रम कुछ ऐसा भी हुआ कि पश्चिमी जगत का आर्थिक और राजनैतिक वर्चस्व निरंतर बढ़ता चला गया। हम उसे अपनाते चले गए और उसी में ही गौरव बोध अनुभव करने की आदत डाल ली। दूसरी और हमारा देशज चिंतन जो स्वयं अपना निजी चिंतन था और हमारे अनुकूल था, हमसे दूर होता हुआ अपरिचित होता गया। महात्मा गांधी के हिन्द स्वराज के स्वर जो १९०९ में उठे थे वे तेज़ी से मद्धिम पड़ने लगे। आर्थिक योजनाएं, शैक्षिक व्यवस्थाएं, सांस्कृतिक नीतियाँ सबकुछ महात्मा गांधी के स्वप्न के विपरीत दिशा में चलने वाला हो चला। परिणाम यह हुआ कि देश के स्वतंत्र होने के बाद भी देश के शैक्षिक आयोजन में गुलामों के लिए बनाया गया पुराना औपनिवेशिक ढाँचा ही बदस्तूर चलता रहा। यदा-कदा कुछ सतही बदलाव लाने का प्रयास जरूर हुआ पर वह आयोजन मुख्य रूप से पश्चिम से आयातित ढाँचा लेकर ही आगे बढ़ता रहा। इसका परिणाम शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भारत के पिछड़ने के रूप में सामने आया। आज भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो चुका है। साथ ही वह ऐसा देश भी है जिसमें युवा वर्ग की जनसंख्या का अनुपात विश्व में सबसे अधिक है। देश के लिए यह निश्चित रूप से लाभ की स्थति हो सकेगी बशर्ते हमारा युवा वर्ग योग्य और कुशल हो। यह चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि भारत वर्ष २०४७ तक विकसित देश की कोटि में आने के लिए तत्पर और प्रयासरत है। इस पूरे परिदृश्य में भारत को समझना, उसे अंगीकार करना आज भी प्रमुख प्रश्न हो जाता है। भारत की अच्छी-बुरी अनेक छवियाँ प्रचलित हैं जो भिन्न भिन्न प्रयोजनों से समय-समय पर गढ़ी गई हैं। एक भौगोलिक संरचना के रूप में किसी देश की परिधि और उपलब्धता राजनैतिक संकल्पों और घटनाक्रमों के साथ भी जुड़ी रहती है। भारत जो कभी अखंड था हम सबके देखते-देखते बीसवीं सदी में ही दो बार खंडित हुआ। पहला विभाजन तब हुआ जब पाकिस्तान बना था और दूसरा तब जब बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुआ। देखें तो भूमि तो वही रही और वहीं रही जहाँ पहले थी परंतु उस भूमि का अर्थ, उपयोग, उससे संबंध और संलग्नता का आशय लगातार बदलता रहा। भारत जो कभी प्रकृति की गोद में समुद्र और हिमालय के बीच स्थित स्वतःसिद्ध इकाई के रूप में स्वीकृत था परिभाषाओं की प्रतीक्षा करने लगा। उसकी अनेक परिभाषाएँ दी जाती रहीं। आज जब एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को हम साकार करने को तैयार हो रहे हैं तो हमें यह भी सोचना होगा हम किस भारत की प्रतिमा के साथ चल रहे हैं। वह भारत कैसा होगा? यह सुखद आश्चर्य है कि उसकी एक अतुल्य छवि डेढ़ सौ साल पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में आए गीत वंदे मातरम् में प्रतिध्वनित हुई थी। प्रकृति की सारी सुषमा से समन्वित, सारी कामनाओं को पूरा करने वाली, मधुर वाणी वाली, निर्मल, अतुलनीय, ज्ञान और शक्ति से परिपूर्ण भारत माता की छवि सारे भेदभावों से परे एक आत्मीय प्रतिमा को रूपायित करती है। इस छवि का स्मरण और मन में धारण करना निजी स्वार्थ से परे सबके लिए समग्र जीवन की दिशा में समर्पण के लिए अग्रसर कराता है।

शिक्षा के क्षेत्र में जो हस्तक्षेप किया गया उसके बड़े दूरगामी परिणाम हुए जिनसे हम आज तक नहीं उबर सके हैं। इस हस्तक्षेप के अंतर्गत भारतीय चिंतन , ज्ञान-परम्परा और भारतीय विश्व दृष्टि को अप्रासंगिक ठहरा कर उसे हाशिये पर डाल दिया गया। भारतीय प्रतिभा , कौशल और ज्ञान संपदा का समूचा अवदान कालबाह्य घोषित कर दिया गया। इस अहैतुक उपेक्षा का सीधा परिणाम यह हुआ कि हमारा आत्मबोध और हमारी पहचान पश्चिम के आलोक में परिभाषित की जाने लगी। पश्चिमी चिंतन वैज्ञानिक और आधुनिक कहलाते हुए मुख्यधारा बनकर हम सब पर थोप दिया गया। दूसरी तरफ़ भारतीय दृष्टि उस मुख्यधारा से विचलन के रूप में अग्राह्य और व्यर्थ मानी जाने जाने लगी। उसकी ओर सतत उपेक्षा और वितृष्णा की प्रवृत्ति ने एक ऐसा माहौल बनाया जो हमें सोच-विचार और अपनी निर्णय- क्षमता के लिए पर निर्भर कर दिया।

एसआईआर का विरोधः चिन्ता लोकतंत्र की या वोट बैंक की?

ललित गर्ग

भारत का लोकतंत्र आज जिस निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, वहां उसकी विश्वसनीयता और मजबूती का सवाल पहले से कहीं अधिक गंभीर हो गया है। चुनावों की पारदर्शिता, मतदाता सूची की शुचिता और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से मतदाता पहचान की सत्यता को बनाए रखना केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को सुरक्षित रखने का मूल तत्व है। विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआईआर इसी उद्देश्य से प्रारंभ की गई वह अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से मतदाता सूची में मौजूद संदिग्ध, दोहरे या अवैध प्रविष्टियों की पहचान और सत्यापन किया जा सके। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस कार्य को लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक कदम माना जाना चाहिए, उसे कुछ विपक्षी दल अपने राजनीतिक हितों के चश्मे से देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार के उतावले, भावनात्मक और अक्सर तथ्यहीन तर्क प्रस्तुत किए गए, उससे यही प्रतीत होता है कि यह विरोध किसी तर्क या सिद्धांत का नहीं, बल्कि वोट-बैंक की चिंता का परिणाम है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर बेतूका राष्ट्र-विरोधही अड़ंगा लगाने वालों को आईना ही दिखाया कि बिहार में तो एक भी व्यक्ति यह शिकायत करने नहीं आया कि उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार में एसआईआर के समय कुछ खास लोगों के वोट काटे जाने का आरोप उछालने वाले भी ऐसे कथित पीड़ित लोगों के उदाहरण का साक्ष्य नहीं दे सके थे। हालांकि बिहार में एसआईआर पर विपक्षी दलों को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन वे बाज नहीं आ रहे हैं और अब 12 राज्यों में जारी एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष खड़े हैं। यह तब है, जब एसआईआर वाले राज्यों में करीब 65 प्रतिशत फार्म भरे जा चुके हैं। इसका मतलब है कि लोग इस प्रक्रिया में बढ़-चढ़ कर भाग ले रहे हैं। एसआईआर होना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि मतदाता सूचियों में भारी त्रुटियां एवं विसंगतियां है, बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के नाम दर्ज हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है या फिर जो अन्यत्र चले गए हैं। इसके अलावा ऐसे भी लोग हैं, जिनके पास दोहरे मतदाता पहचान पत्र हैं। चुनाव आयोग एसआईआर के जरिये इन्हीं विसंगतियों को दूर कर रहा है, लेकिन विपक्षी दलों को पता नहीं क्यों यह रास नहीं आ रहा है। वे मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की शिकायत भी कर रहे हैं और एसआईआर भी नहीं होने देना चाहते है। लोकतंत्र की जड़ों में सबसे बड़ा विष तब घुलता है जब मतदाता सूची अवैध हस्तक्षेपों, बाहरी घुसपैठियों और राजनीतिक संरक्षण के सहारे खड़ी प्रविष्टियों से दूषित होने लगती है। भारत लंबे समय से विदेशी घुसपैठ की समस्या से जूझ रहा है। राज्यों के बीच असंतुलित प्रवासन, सीमावर्ती क्षेत्रों में बेतरतीब आबादी का फैलाव, राजनीतिक शरण और संरक्षण के नाम पर अवैध बसेरों का निर्माण-ये सब ऐसी वास्तविकताएं हैं जिन्हें अनदेखा करना राष्ट्रहित से खिलवाड़ है। एसआईआर की प्रक्रिया इसीलिए आरंभ की गई कि मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध, विश्वसनीय, पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित बनाया जा सके। यह प्रक्रिया किसी समुदाय, क्षेत्र या वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि व्यक्तिगत पहचान के सत्यापन पर आधारित है। यह समान रूप से हर उस मतदाता की जांच करती है जो कानूनन इस प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके बावजूद विपक्ष द्वारा इसे अधिकारों पर हमला, राजनीतिक भेदभाव या अविश्वास की राजनीति से जोड़ना केवल दुष्प्रचार एवं भोलेभाले लोगों को गुमराह करना है। यह सवाल इसलिए उठता है कि जब प्रक्रिया सबके लिए समान है, सभी क्षेत्रों पर लागू है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में संचालित हो रही है, तो किस आधार पर इसे लोकतंत्र विरोधी कहा जा सकता है? वास्तव में विपक्ष इस प्रश्न का ठोस, तथ्यपूर्ण उत्तर देने में असफल रहा है। यह आशंका निराधार नहीं कि बंगाल जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए मतदाता बन बैठे हैं। उनके बांग्लादेश लौटने से इसकी पुष्टि भी होती है। यह ठीक है कि पहचान पत्र के रूप में आधार भी मान्य है, लेकिन उसे भी फर्जी तरीके से बनवाया गया हो सकता है। ऐसे में चुनाव आयोग को दस्तावेजों के सत्यापन का अधिकार मिलना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत विपक्षी तर्कों का विश्लेषण करें, तो उनमें वास्तविक तथ्यों एवं आंकड़ों का अभाव है। भावनात्मक अपीलें, आशंकाओं का जानबूझकर सृजन, प्रशासनिक प्रक्रिया को अविश्वसनीय बताने का प्रयास, और तथ्यों से अधिक आरोपों का शोर-ये सब इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक जमीन को बचाना है। यदि मतदाता सूची वास्तव में त्रुटिरहित है, यदि घुसपैठियों का प्रश्न बिना आधार का है, यदि किसी वर्ग की वैधता पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं, तो फिर सत्यापन से भय क्यों? सत्यापन तो वही व्यक्ति या समूह टालेगा, जो स्वयं को संदेह के घेरे में पाता हो। जो स्वच्छ, वैध और तथ्यपूर्ण हैं उन्हें कभी डर नहीं होता कि जांच उनके लिए समस्या बन जाएगी। इसलिए यह विरोध लोकतंत्र की चिंता नहीं बल्कि लोकतंत्र का उपयोग करके अपने हित साधने की कोशिश प्रतीत होता है। भारत की चुनाव प्रणाली में वर्षों से यह शिकायत उठती रही है कि मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियां, मृत व्यक्तियों के नाम, काल्पनिक मतदाता और बाहरी लोगों की अवैध प्रविष्टियां बढ़ती जा रही हैं। इनमें से अधिकांश समस्याएं प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा ऐसे राजनीतिक हितों का भी है जो ऐसी प्रविष्टियों को बनाए रखने में खुद को लाभान्वित देखते हैं। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं कि भारत के अनेक राज्यों में स्थानीय राजनीतिक तंत्र विदेशी घुसपैठियों के लिए न केवल छत्रछाया प्रदान करता रहा है, बल्कि उन्हें वोट-आधारित पहचान और सुविधाओं तक पहुंच भी दिलाता रहा है। इन परिस्थितियों में एसआईआर जैसी प्रक्रिया न केवल उचित है, बल्कि अत्यंत आवश्यक है। यह प्रक्रिया जितनी देर से लागू होगी, लोकतंत्र पर उतना ही खतरा बढ़ेगा। एसआईआर के विरोध का एक और पक्ष भी है, और वह है विपक्ष का यह डर कि यदि मतदाता सूची शुद्ध कर दी गई, तो उनका चुनावी गणित प्रभावित होगा। यह राजनीति का वह पक्ष है जिसमें आदर्शवाद के लिए बहुत कम जगह है। राजनीतिक दल अक्सर यह मानकर चलते हैं कि जहां संख्या उनके पक्ष में है, वहां सुधार का कोई हस्तक्षेप उनकी स्थिति को कमजोर कर सकता है। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र की आत्मा के विरुद्ध है, क्योंकि लोकतंत्र केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि नागरिक विश्वास और संवैधानिक मूल्यों का संरक्षक है। एसआईआर का उद्देश्य किसी को मताधिकार से वंचित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि मताधिकार का उपयोग वही करे जो इसके योग्य है, जो देश का वैध नागरिक है, और जिसका नाम सही तरीके से मतदाता सूची में दर्ज है। भारत का भविष्य उन सुधारों पर निर्भर करता है जो चुनावों को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाएं। जब तक मतदाता सूची शुद्ध नहीं होगी, तब तक चुनाव परिणामों पर संदेह रहेगा और लोकतंत्र की साख कमजोर होती जाएगी। एसआईआर इस दिशा में उठाया गया साहसिक कदम है, जिसे किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव या भ्रम फैलाने वाले अभियानों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह प्रक्रिया और अधिक निष्पक्ष और संरक्षित होती है, इसलिए विरोध के ये प्रयास और भी आधारहीन प्रतीत होते हैं। लोकतंत्र की मरम्मत और मजबूती का यह अवसर खोना राष्ट्रहित के विरुद्ध होगा। जो दल इस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे भले ही इसे जनता के हित का मुद्दा बताने का प्रयास करें, परंतु वस्तुतः वे अपने संकीर्ण हितों की रक्षा कर रहे हैं। भारत को ऐसी राजनीति की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जो सत्य को प्राथमिकता दे, सत्ता से अधिक संविधान को महत्व दे, और मतदाता सूची को राजनीतिक हथियार नहीं बल्कि लोकतंत्र की पवित्र सूची माने। एसआईआर की गति और दायरा इसलिए न केवल बनाए रखना चाहिए, बल्कि उसे और भी तेज, निर्णायक और प्रभावी बनाना चाहिए, ताकि भारत का लोकतंत्र अवैध प्रभावों से मुक्त होकर एक मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय भविष्य की ओर अग्रसर हो सके।

एसआईआर की प्रक्रिया इसीलिए आरंभ की गई कि मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध, विश्वसनीय, पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित बनाया जा सके। यह प्रक्रिया किसी समुदाय, क्षेत्र या वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि व्यक्तिगत पहचान के सत्यापन पर आधारित है। यह समान रूप से हर उस मतदाता की जांच करती है जो कानूनन इस प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके बावजूद विपक्ष द्वारा इसे अधिकारों पर हमला, राजनीतिक भेदभाव या अविश्वास की राजनीति से जोड़ना केवल दुष्प्रचार एवं भोलेभाले लोगों को गुमराह करना है।

युवा सम्मेलन में गूंजा आत्मनिर्भर भारत का संदेश

● स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर दिया जोर

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

कछौना (हरदोई)। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से नगर स्थित बाबा कुशीनाथ मंदिर के प्रांगण में शुक्रवार को युवा सम्मेलन उत्साह पूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ! जिसमें नगर व क्षेत्र से बड़ी संख्या में युवाओं शिक्षकों सामाजिक कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया! कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में स्वावलंबन, कौशल विकास, स्वदेशी उपयोग, आत्मनिर्भर और रोजगार सृजन के प्रति जागरूक करना रहा! कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं से आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प पत्र भी भरवाए गए! कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि व प्रदेश कार्य समिति सदस्य (भाजयुमो) संचित अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा है! आज अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है जो कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बहुत जल्द प्रथम स्थान पर होगा व वर्ष 2047 तक भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र बनेगा! कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मंडल अध्यक्ष मयंक सिंह ने कहा कि देश की प्रगति के आधार उसके युवा हैं और आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी पूरा होगा जब युवा कौशलपूर्ण आत्मविश्वासी और नवाचार के प्रति प्रेरित होंगे! सम्मेलन के अंत में आयोजकों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं में नई ऊर्जा का संचार करते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं! भारत माता की जय बंदे मातरम जैसे देशभक्ति के नारों के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ! कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा जिला मंत्री अजय शुक्ला, जिला कार्य समिति सदस्य ब्रह्म कुमार सिंह, अनूप दीक्षित,अजय बाजपेई, संजय सिंह, सुनील सोनी, शौर्य वर्धन सिंह, नारायण शुक्ला, शिरीष मिश्रा, प्रतीक गुप्ता, अनूप गुप्ता और विकास गुप्ता सहित सैकड़ो युवाओं ने उपस्थित होकर आत्मनिर्भर भारत का एक स्वर में संकल्प लिया।

आधार नामांकन केंद्र पर कई महीनो से ताला, आम जनता परेशान

कछौना, (हरदोई) ब्लाक संसाधन केंद्र (बीआरसी) कछौना के प्रांगण में संचालित आधार नामांकन केंद्र पिछले कई महीनो से बंद पड़ा है! जिस कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है! केंद्र के दरवाजे पर लंबे समय से ताला लटक रहा है जिससे नए आधार कार्ड बनवाने, संशोधन कराने, अपडेट, बच्चों के नामांकन, पते में सुधार जैसी अति आवश्यक सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई है! चूँकि वर्तमान समय में आधार कार्ड प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता बन गया है जिसके बिना नागरिकों को मिलने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाएं/सुविधाएं जैसे बैंकिंग, जीएसटी, पेंशन, किसान सम्मान, छात्रों के काम व अन्य आवश्यक कार्य बुरी तरह प्रभावित होते हैं! केंद्र बंद होने से रोजाना नगर व दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, महिलाएं व बुजुर्ग चक्कर लगाते हैं और निराश होकर लौट जाते हैं! लोगों का कहना है कि किसी भी प्रकार की आधिकारिक सूचना न मिलने से वह उलझन में है कि केंद्र दोबारा कब खुलेगा या नहीं खुलेगा!

श्रीमद्‌भागवत कथा में श्रीराम विवाह महोत्सव का आयोजन

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

पिहानी (हरदोई)। माँ इच्छापूर्णी रामजानकी मन्दिर में चल रही श्रीमद्‌भागवत कथा के आठवें दिवस पर पूज्य प्रकाश चंद्र महाराज ने कथा को संबोधित करते हुए कहा, कि साधारण जीवों को श्री कृष्ण के चरित्र पर संदेह हो सकता है लेकिन यदि आप लीला पुरुषोत्तम को समझना चाहते हैं तो आपका श्री राधा जी में निष्ठ प्रेम होना चाहिए तभी आप समझ पायेंगे।

आचार्य ने कहा, कि भगवान श्रीकृष्ण की 8 पत्नियां थी। जो रुक्मणि, जाम्बवन्ती, सत्यभामा, कालिन्दी, मित्रबिन्दा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। महाभारत के अनुसार रुक्मणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर उनके साथ विवाह रचाया था। सूर्य पुत्री कालिन्दी, श्रीकृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप किया। तब कालिन्दी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्रीकृष्ण ने उसके साथ विवाह किया।

फिर वे एक दिन उज्जयिनी की राजकुमारी मित्रबिन्दा को स्वयंवर से हर लाए। उसके बाद कौशल के राजा नग्नजित के सात बैलों को एक साथ नाथ कर उनकी कन्या सत्या से विवाह किया। तत्पश्चात उनका कैकेय की राजकुमारी भद्रा से विवाह हुआ। भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी कृष्ण को चाहती थी, लेकिन परिवार कृष्ण से विवाह के लिए राजी नहीं था तब लक्ष्मणा को श्रीकृष्ण अकेले ही हर कर ले आए। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और उन सभी कन्याओं को कैद से मुक्त करा दिया, जब वह सब अपने घर पहुंची तो परिवार वालों ने उनको अपनाने से मना कर दिया। लोकलाज के भय से मरने को व्याकुल कन्याओं को श्री कृष्ण ने 16 हजार रूपों में प्रकट होकर एक साथ उनसे विवाह रचाया। भगवान की सभी लीलाओं में गूढ़ भाव होता है, जो साधारण मनुष्यों की समझ में आने वाला नहीं है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से मंदिर महंत वैष्णव हरिशरण महाराज, रामसेवक रस्तोगी, लल्लन रस्तोगी, जगदीश प्रसाद शुक्ला, कृष्णपाल जोशी, अखिलेश मिश्रा, धर्मेंद्र सोनी समेत भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

इतिहास से छेड़छाड़ करते हुए प्रदेश में लगाये जा रहे अवैध होर्डिंग व पोस्टर

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

हरदोई। सुनील अर्कवंशी कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि (मध्याचंल) राष्ट्रीय प्रवक्ता-सुभासपा पूर्व सदस्य-राज्य एकीकरण परिषद उत्तर प्रदेश ने जिलाधिकारी को दिए हुए पार्थना पत्र में कहा हमारे समाज के महाराजा सल्हीय सिंह अर्कवंशी जी के इतिहास से छेड-छाड़ कर कुछ अराजक तत्वों द्वारा अखिल भारतीय पासी महासभा द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अर्कवंशी समाज के महाराजा सल्हीय सिंह अर्कवंशी के नाम से छेड-छाड़ कर सल्हीया पासी के नाम से होर्डिंग पोस्ट लगाये गये हैं तथा समाज को इस कार्य से भ्रमित करने का प्रयास किया गया है तथा उक्त कृत्य से समाज में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमारे समाज के महाराजा की छवि धूमिल कर उनका इतिहास मिटाने का यह षडयंत्र कुछ अराजक तत्वों द्वारा किया जा रहा है। महाराजा सल्हीय सिंह अर्कवंशी के जन्म दिवस पर विभिन्न संगठनों, मंत्रियों, सांसद, विधायकों द्वारा धूमधाम से सोशल मीडिया व प्रिन्ट मीडिया पर बधाई संदेश दिया गया है। उसके बावजूद अखिल भारतीय पासी महासभा द्वारा हमारे महाराज की जाति से छेड़छाड़ की जा रही है। जिससे हमारे समाज में काफी आक्रोश व्याप्त हो रहा है। यदि उक्त संगठन व उसके पदाधिकारियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी तो समाज आन्दोलन करने के लिए विवश होगा। यदि 24 घण्टे के भीतर उपद्रवियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो हमारा समाज आन्दोलन करने के लिए विवश होगा।

आयुक्त ने बबेरू में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यों का किया निरीक्षण

बांदा। चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा के आयुक्त अजीत कुमार ने आज तहसील बबेरू में संचालित विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसील सभागार में लगभग 60 कर्मचारी डिजिटाइजेशन कार्य में सक्रिय रूप से लगे पाए गए। उपजिलाधिकारी बबेरू ने आयुक्त को वर्तमान प्रगति से अवगत कराते हुए बताया कि अब तक डिजिटाइजेशन का कार्य 52 प्रतिशत पूरा हो चुका है तथा प्रयासरत टीम इसे कल तक 60 प्रतिशत तक पहुँचाने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है। इस पर आयुक्त ने प्रगति को और तेज गति से आगे बढ़ाने के निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने दो भाग संख्या 121 (मुरवल) के श्री उमेश कुमार तथा भाग संख्या 348 (पिस्टा) के बालमुकुंद तिवारी के कार्यों का विशेष रूप से अवलोकन किया, जिनकी प्रगति क्रमशः 18 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत पाई गई।

खनिज विभाग के के लिए नासूर बना मरौली खण्ड पांच का अवैध खनन

● पिछले सत्र में पांच बार कार्यवाही होने के बाद भी हालात जस के तस

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

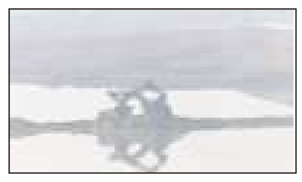

बांदा। लगातार कई वर्षों से अवैध खनन सहित कई अन्य घिनौने कार्यों को लेकर विवादों में रहने वाली मरौली खण्ड पांच में अवैध खनन इस सत्र में भी लगातार धड़ल्ले से जारी है। पिछले सत्र में पांच पर संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही होने के बाद भी खदान संचालक के गुर्गे सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस सत्र में भी मरौली पांच खदान का अवैध खनन खनिज विभाग सहित प्रशासन के लिए नासूर बनता जा रहा है। खदान संचालक की पहुंच के चलते काई भी जिम्मेदार इस खदान में हाथ डालने को तैयार नहीं है। जानकारी के अनुसार अंतर्गत मरौली खदान खंड संख्या 5 में दिन पे दिन दिन रात भारी भरकम मशीनों के साथ बड़े-बड़े गड्ढों को खोद कर लाल सोना निकाला जा रहा है यह खदान पिछले सत्र भी अवैध खनन के चर्चा में जग जाहिर रही है जिसमें भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया था लेकिन खदान माफिया के रसूक पकड़ के चलते इस बार नए सत्र में शुरुआती दौर से ही अवैध खनन का सिलसिला इस खदान में देखने को मिल रहा है मजाल है कि कोई जिम्मेदार अधिकारी इस खदान की तरफ आंख उठाकर देख सके रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक में अवैध तरीके से खनन कार्य को अंजाम दिया जा रहा है लगातार कई समाचार पत्र व टीवी चौनल इस खदान की अवैध खनन परिवहन की खबरें लगातार प्रकाशित कर रहे हैं दिखा रहे है लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इस खदान में अवैध खनन दिखाई नहीं दे रहा आप जीपीएस फोटो में देख सकते हैं कि किस कदर भारी भरकम गड्ढे बड़ी-बड़ी मशीनों के खोदे जा रहे हैं यही गड्ढे इंसानों व जानवरों के लिए बड़े हादसे का शिकार बनते हैं। अगर अभी से इस तरह के अवैध खनन में लगाम नहीं लगाई गई तो आगे आने वाले समय में यह माफिया इतना हावी हो जाएगा कि लोगों की निजी जमीनों तक को खोदने में गुरेज नहीं करेगा उनको तो बस अपनी कमाई से मतलब है चाहे सरकार का लाखों का राजस्व तबाही हो या किसी की जिंदगी की तबाही हो उन्हें इस चीज से कोई लेना-देना नहीं है अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अब भी कोई जिम्मेदार अधिकारी इस तरफ अपनी नजर डालते हैं या फिर अपने लग्जरी आफिसों में बैठकर कार्यवाही करने अपनी वाहवाही का दंभ भरते रहेंगे।

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्रतिनिधिमंडल ने सांसद को सौंपा ज्ञापन

बांदा।राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ बांदा एवं चित्रकूट जनपद के जिला अध्यक्षों सहित प्रतिनिधि मंडल ने बांदा चित्रकूट सांसद श्रीमती कृष्णा देवी शिव शंकर पटेल को उनके आवास पर ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जनपद बांदा के जिला अध्यक्ष पंकज सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के आवाहन पर उत्तर प्रदेश के समस्त सांसदों को टी ई टी प्रकरण के संबंध में 1 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद सत्र में मांग रखने हेतु ज्ञापन सौंपा गया है। जिसके क्रम में आज जनपद चित्रकूट एवं बांदा के प्रतिनिधिमंडलों द्वारा बांदा चित्रकूट सांसद श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल को ज्ञापन सौंप कर टी ई टी लागू होने से पूर्व से नियुक्त शिक्षकों को टी ई टी अनिवार्य करने से मुक्त रखने हेतु संसद के शीतकालीन सत्र में मांग रखने का आग्रह किया गया। दोनों जिला अध्यक्षों द्वारा सांसद महोदया को इस प्रकरण पर विस्तार से समझाते हुए संसद सत्र में टीईटी संबंधी अध्यादेश में संशोधन करते हुए लाखों शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की मांग रखने का आग्रह किया गया।

डीएम ने मंडी परिषद उन्नाव के धान क्रय केंद्रों का किया निरीक्षण

● केंद्र प्रभारी को खरीद बढ़ाने, किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ दिलाने के निर्देश

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

उन्नाव : जिलाधिकारी गौरांग राठी ने मंगलवार को मंडी परिषद उन्नाव में संचालित विपणन शाखा खाद्य विभाग के धान क्रय केंद्र प्रथम और द्वितीय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने धान खरीद की वर्तमान स्थिति, किसानों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं और क्रय केंद्रों के लक्ष्य की समीक्षा कर केंद्र प्रभारियों को खरीद बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान डीएम ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ हर हाल में किसानों तक पहुँचे, इसके लिए सभी क्रय केंद्र अपने निर्धारित लक्ष्य समय से पूरा करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि किसानों को भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर ही उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसी किसान को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। जिलाधिकारी ने क्रय केंद्रों पर नमी मापक यंत्र, जूट के बोरे, इलेक्ट्रिक कांटा, एनालिसिस किट, किसानों के पंजीकरण, भुगतान की स्थिति, तौल व्यवस्था और किसानों के बैठने व पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की भी गहन समीक्षा की।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी किसान के साथ दुर्व्यवहार न हो और केंद्र पर सभी सुविधाएँ व्यवस्थित रहें।

डीएम ने क्रय केंद्र प्रभारी को बड़े काश्तकारों व ग्राम प्रधानों से संपर्क कर अधिक से अधिक किसानों को धान बेचने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन की खरीद की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। उप जिलाधिकारी व लेखपाल को भी निर्देशित किया गया कि किसान पंजीकरण का सत्यापन पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए।

डिप्टी आरएमओ संतोष कुमार यादव ने बताया कि जनपद में 35,000 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से 1,698.78 मीट्रिक टन खरीद की जा चुकी है। जनपद में कुल 39 क्रय केंद्र संचालित हैं।

मंडी परिषद के क्रय केंद्र प्रथम में 134.54 मीट्रिक टन तथा द्वितीय में 118.28 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। उन्होंने बताया कि धान का एमएसपीऽ सामान्य धान 2369 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान 2389 रुपये प्रति क्विंटल तय है, जबकि उतराई-छनाई हेतु 20 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित हैं। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सुशील कुमार गोंड़, उप जिलाधिकारी क्षितिज कुमार द्विवेदी, डिप्टी आरएमओ संतोष कुमार यादव सहित अन्य संबंधित अधिकारी व क्रय केंद्र प्रभारी मौजूद रहे।

अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत

उन्नाव। अचलगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात हुए सड़क हादसे में 29 वर्षीय युवक आशीष पुत्र बिंदा प्रसाद निवासी पचोद्दा की मौत हो गई। आशीष काम से लौटकर पैदल घर जा रहा था, तभी सिकंदर करण के पास बने ब्रिज पर एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि आशीष की मौके पर ही मौत हो गई। मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करने वाले आशीष की मौत से घर में कोहराम मचा है। कुछ वर्ष पहले बड़े भाई की ट्रेन हादसे में मौत हो चुकी है। अब छोटे बेटे के निधन से पिता बिंदा प्रसाद समेत पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों ने बताया कि आशीष शांत स्वभाव और मिलनसार था। उसकी शादी हुई थी, लेकिन वैवाहिक संबंध टूटने के बाद वह अकेले रहकर मजदूरी कर रहा था। स्थानीय लोगों के अनुसार, सिकंदर करण ब्रिज के पास वाहनों की तेज रफ्तार के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

वांछित अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए: डीआईजी

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

बांदा। पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा राजेश एस. की अध्यक्षता में परिक्षेत्र के पुलिस अधीक्षकों के साथ पुलिस लाइन्स बांदा में अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया । बैठक में महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रचलित अभियान मिशन शक्ति फ़ेज-5.0 में कार्यवाही के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए । परिक्षेत्र के सभी जिलों में घटित अपराधों की समीक्षा की गई । हत्या, लूट, चोरी, महिला अपराध, साइबर अपराध, यातायात दुर्घटनाएं, बैंकों एवं लेन-देन के स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जाय व जनता की शिकायतों का त्वरित व प्रभावी रुप से निस्तारण किया जाए । आई0जी0आर0एस0 से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण किया जाए । वांछित अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए ।

’ महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रचलित अभियान मिशन शक्ति फ़ेज-5.0 में कार्यवाही के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए ।साइबर अपराध पर अंकुश लगाने हेतु सभी जनपदों में संचालित साइबर थानों द्वारा त्वरित कार्यवाही एवं आमजन को जागरुक करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश ।अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही, गैगस्टर अधि0 व गुंडा अधिनियम की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।आपरेशन त्रिनेत्र/दृष्टि के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश ।गंभीर अपराधों की विवेचना में गुणवत्ता एव समयबद्धता सुनिश्चित की जाए ।संवेदनशील स्थानों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, सर्राफा बाजार, कस्बों, चौराहों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन आदि पर विशेष सतर्कता रखते हुए सुरक्षा हेतु प्रभावी प्रबंधन एवं विशेष सतर्कता बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया।

अब्बास बाग मोहल्ले में दुर्गंध बढ़ी, बीमारियों का खतरा

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

● शिकायत के बाद भी ईओ की लापरवाही से मोहल्लेवासियों में आक्रोश

शुक्लागंज(उन्नाव)। नगर पालिका शुक्लागंज में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के आरोप फिर सामने आए हैं। वार्ड नंबर 29 स्थित अब्बास बाग मोहल्ले में कूड़ा गाड़ी पिछले चार दिनों से नहीं पहुंची है। नगर पालिका द्वारा कूड़ा गाड़ी के पेट्रोल और डीजल के लिए बजट जारी होने के बावजूद सफाई व्यवस्था ठप पड़ी है।

मोहल्ले में कूड़ा न उठने से रास्तों और गलियों में गंदगी का अंबार लग गया है। लगातार बढ़ रही दुर्गंध के कारण लोगों को घरों में रहना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि गंदगी के कारण कई संक्रामक रोग फैलने का खतरा बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही।

संवाददाता से बातचीत करने पर सफाई इंस्पेक्टर रश्मि पुष्कर ने बताया मामला संज्ञान में आया है कल ही इसको दिखाकर समस्या का समाधान करवाया जाए।

ईओ नगर पालिका संजय गौतम ने संवाददाता से बातचीत में बताया कि मामला संज्ञान में आया है कूड़ा गाड़ी को भिजवाकर समस्या का समाधान करवाया जाएगा

मोहल्ले वासियों ने ईओ और सफाई इंस्पेक्टर से शिकायत की, लेकिन आरोप है कि अधिकारियों ने केवल बयानबाजी करते हुए ‟करवा देंगे” कहकर पल्ला झाड़ लिया। इससे नाराजगी बढ़ गई है। निवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सफाई नहीं हुई तो वे ईओ के खिलाफ जिला प्रशासन को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग करेंगे।

उन्नाव: नाबालिग बालिका के शादी होने से पहले बाल कल्याण समिति ने बचाया

उन्नाव। बाल कल्याण समिति के पत्र के माध्यम से चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना मिली कि ग्राम सलखेंमऊ, पोस्ट मोहान, थाना हसनगंज की एक नाबालिग बालिका का विवाह 1 दिसंबर 2025 को उनके निवास स्थान सलखेंमऊ, वार्ड नंबर 1 मोहान, हसनगंज पर होने वाला था। चाइल्ड हेल्पलाइन प्रो कोर्डिनेटर दिवाकर ओझा ने उच्च अधिकारियों को तत्काल जानकारी दी। जिला प्रोबेशन अधिकारी क्षमा नाथ राय के आदेशानुसार चाइल्ड हेल्पलाइन टीम और थाना हसनगंज चौकी सलखेमऊ की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर देखा गया कि बालिका के विवाह की तैयारी हो रही थी। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने नाबालिग बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। बाल कल्याण समिति ने तुरंत अग्रिम कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका को वन स्टॉप सेंटर में दाखिल किया। समिति ने बालिका की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जानकारी दी।

एसआईआर सर्वे में सहयोग करें, डीएम उन्नाव की नागरिकों से अपील

● बीएलओ कर रहे घर-घर फॉर्म भरने का प्रयास, नागरिकों से समय पर जानकारी देने की अपेक्षा

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

उन्नाव। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने शहरी क्षेत्रों में एसआईआर सर्वे का निरीक्षण करने के बाद नागरिकों से सहयोग की अपील की है। डीएम ने कहा कि बीएलओ लगातार घर-घर जाकर फॉर्म भरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई स्थानों पर लोगों की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है।

जिलाधिकारी गौरांग राठी ने बताया, ‟आज हमने दो शहरी बूथों का निरीक्षण किया। यहाँ जो समस्याएँ सामने आईं, वे ग्रामीण इलाकों से अलग हैं। बीएलओ और बीएलए से फीडबैक लिया गया। मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूँ कि यह एक सामूहिक प्रक्रिया है। बीएलओ आपके द्वार पर कई-कई बार आते हैं, इनमें कई महिलाएँ भी शामिल हैं। कृपया सहयोग करें और समय से फॉर्म उपलब्ध करा दें, ताकि डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा हो सके। अक्सर देखा गया है कि कई लोगों के नाम अलग-अलग स्थानों पर एक साथ दर्ज हैं। ऐसे में नागरिक स्वयं जानकारी दें कि उनका वास्तविक निवास स्थान कौन सा है, ताकि अन्य जगहों से नाम हटाया जा सके। यह पूरी तरह सामान्य प्रक्रिया है और इसमें कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। जहाँ आप वर्तमान में निवास करते हैं, वहीं आपका नाम रहेगा। शहरी क्षेत्र में बिना घर-घर जाए जानकारी लेना संभव नहीं है। इसलिए घरों के विजिट के दौरान सहयोग की अपेक्षा है। डीएम ने यह भी बताया कि सहायता केंद्रों पर कोटेदार, आंगनवाड़ी, आशा और फील्ड स्टाफ तैनात हैं। यदि नागरिक एक कदम आगे बढ़ेंगे, तो पूरी प्रक्रिया और सुचारू रूप से पूरी हो सकेगी।

बढ़ती ठंड में कंपकपा रहे गोवंश, पालिका ने लगाए तिरपाल

शुक्लागंज, उन्नाव। नवंबर के अंतिम दिनों में शाम के बाद पारा गिरने से ठंड और गलन बढ़ गई है। शुक्लागंज के गगनी खेड़ा स्थित कान्हा गौशाला में संरक्षित सैकड़ों गोवंश ठंड से प्रभावित हो रहे हैं। बेजुबानों को ठिठुरन से बचाने के लिए शनिवार को पालिकाध्यक्ष कौमुदी पांडेय और ईओ मुकेश मिश्रा के निर्देश पर नगर पालिका ने त्वरित कार्रवाई की।

पूर्वोत्तर रेलवे
निविदा सूचना सं. 11 वर्ष 2025-26
₹ 3,72,05,375.06
22/12/2025
http://www.ireps.gov.in

बच्चों की सुरक्षा पर एसजेपीयू-एएचटीयू की समन्वय बैठक

एसओपी के पालन पर दिए निर्देश

- बच्चों से जुड़े मामलों में पुलिस को और ज्यादा संवेदनशील व सक्रिय होने पर बल

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखीमपुर खीरी। रिज़र्व पुलिस लाइन स्थित संगोष्ठी कक्ष में शनिवार को एसजेपीयू एवं एएचटीयू की मासिक समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक पुलिस अधीक्षक खीरी के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) की देखरेख और एडीजे वीरेंद्र नाथ पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बच्चों से जुड़े मामलों में पुलिस द्वारा की जाने वाली वैधानिक कार्रवाई के लिए मुख्यालय द्वारा जारी ट्टग्घ का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही थानों पर तैनात बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को आने वाली समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में सीडब्ल्यूसी, जे.जे.बी., स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, चाइल्डलाइन, जिला बाल संरक्षण इकाई, वन स्टॉप सेंटर, जीआरपी समेत सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में बाल श्रम, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति, बाल गुमशुदगी, नशामुक्ति अभियान, लैंगिक समानता व पीड़ित बच्चों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों पर अंतर-विभागीय समन्वय को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा POCSO Act के तहत एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर सीडब्ल्यूसी को सूचना देना क्क्षन्द्ध इ एवं उ समय पर भेजना ख्ख इदप् के मामलों में पुलिस को सादे वस्त्रों में किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना।

उच्च न्यायालय से जारी बेल नोटिस समय से पीड़िता/वादी तक पहुँचाना जैसे प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बच्चों से जुड़े मामलों में लापरवाही या देरी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के अंत में सभी विभागों को समयबद्ध कार्रवाई व बेहतर तालमेल के साथ कार्य करने की अपील की गई।

थाना हैदराबाद पुलिस ने दो वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

अजान खीरी। पुलिस अधीक्षक खीरी संकल्प शर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत, थाना हैदराबाद पुलिस ने दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार अभियुक्तों में दीनदयाल पुत्र जयराम निवासी ग्राम सेमरई और उमेश पुत्र बहादुरलाल निवासी ग्राम पन्नापुर शामिल हैं। दीनदयाल वाद संख्या 698/20 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 में वांछित था, जबकि उमेश मु0अ0सं0 606/25 धारा 60 कड्ड इदप् में वांछित था। गिरफ्तारी टीम में उ0नि0 अशोक कुमार सिंह, उ0नि0 खेमेन्द्र कुमार, हे0का0 शैलेन्द्र सिंह, का0 सचिन कुमार और का0 शिवेन्द्र कुमार शामिल थे। गिरफ्तार अभियुक्तों को आगे की विधिक कार्यवाही के लिए न्यायालय खीरी के समक्ष पेश किया जाएगा।

मेडिकल व्यवसाई के घर मे लूटकांड में शामिल युवक मुठभेड़ में गिरफ्तार

- तेज तर्रार नवागत थानाध्यक्ष की कार्यशैली से अपराधियो में खौफ का माहौल

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

गोला गोकर्णनाथ खीरी। थाना नीमगांव की चौकी सिकन्दराबाद क्षेत्र अन्तर्गत वीते दिनांक 15. नवंबर की रात्रि में मेडिकल स्टोर संचालक को परिवार सहित बंधक बनाकर डकैती करने की घटना के सम्बन्ध में थाना नीमगांव में मु0अ0सं0 488/25 धारा 310(2)/ 317(3) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था। जिसके पश्चात कई पुलिस टीमें लगातार दबिश देकर घटना के अनावरण हेतु प्रयासरत थी। दिनांक 27 नवंबर को उक्त घटना मे शामिल 4 अभियुक्तगणो 1.मुहीब पुत्र असलम उम्र करीब 25 वर्ष नि0 ग्राम कौढेय्या थाना फरधान, 02. हसरत अली उर्फ छोटा तालिब पुत्र बरकत अली उम्र करीब 20 वर्ष नि0 ग्राम गौरिया थाना फरधान, 3.गोपाल वर्मा पुत्र पप्पू वर्मा उम्र करीब 32 वर्ष नि0 पलिया थाना पलिया 4. तैय्यब खां पुत्र रफीक खाँ उम्र करीब 24 वर्ष नि0 ग्राम गौरिया थाना फरधान को पुलिस मुठभेड़ के उपरान्त गिरफ्तार करने मे सफलता हासिल की है।

उक्त अपराधियों के साथ घटना में शामिल वांछित अभियुक्त राजू उर्फ हासिम पुत्र लियाकत उम्र 40 वर्ष निवासी थाना मितौली जिस पर लूट, डकैती, हत्या के प्रयास व गैंगस्टर सहित कुल 36 मुकदमे जनपद खीरी, सीतापुर, बहराइच के विभिन्न थानो मे पंजीकृत है। जोकि अत्यधिक खूंखार व शातिर प्रवृत्ति का अभ्यस्थ अपराधी है। जो नेपाल राष्ट्र मे भी आपराधिक कृत्यो मे सक्रिय है। पुलिस अधीक्षक खीरी द्वारा उक्त अभियुक्त पर 25000 रूपये का ईनाम भी घोषित किया गया था। विती रात दिनांक 29.11.2025 को पुलिस गस्त के दौरान उक्त अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर करके भागने का प्रयास किया जा रहा था पुलिस मुठभेड के दौरान बाये पैर मे गोली लगने से घायल हो गया। जिसके पास से 01अदद तमंचा .315 बोर नाजायज व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज व 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर व 01 अदद मो0सा0 स्पलैंडर बरामद हुई, वही अभियुक्त को हिरासत पुलिस लेकर चिकित्सय सुविधा के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।

थाना हैदराबाद पुलिस ने शान्ति भंग करने वाले 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

अज़ान खीरी। पुलिस अधीक्षक खीरी संकल्प शर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत, अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी के मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष थाना हैदराबाद सुनील मलिक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शान्ति भंग करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में योगेश तिवारी, आकाश वर्मा, मूल्लू और मनोहरलाल शामिल हैं, जो खीरी जिले के विभिन्न गांवों के निवासी हैं। पुलिस ने इन्हें धारा 170/126/135 के तहत गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में व0उ0नि0 सन्तापाल सिंह राठौर, उ0नि0 खेमेन्द्र कुमार, उ0नि0 अशोक कुमार सिंह, का0 सचिन कुमार, का0 शिवेन्द्र कुमार और का0 तरुण कुमार सिंह शामिल थे।

मैलानी मंडल में 'मन की बात' कार्यक्रम की तैयारियाँ पूरी

मैलानी खीरी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला नेतृत्व के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम ह्लमन की बातङ्क का सामूहिक श्रवण कार्यक्रम मैलानी मंडल के सभी बूथों पर आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 30 नवंबर 2025, दिन रविवार, प्रातः 11:00 बजे से एक साथ सभी बूथों पर सम्पन्न होगा। मैलानी मंडल अध्यक्ष संजीव वर्मा ने बताया कि शक्ति केंद्र प्रभारी, शक्ति केंद्र संयोजक, बूथ अध्यक्ष, सभी मोर्चा एवं प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, मंडल में निवासरत पूर्व व वर्तमान जिला पदाधिकारी समेत मंडल के सभी कार्यकर्ता निर्धारित समय पर उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। मंडल महामंत्री एवं संयोजक मिथलेश मिश्रा तथा मंडल महामंत्री रमन सोनी ने भी सभी कार्यकर्ताओं से मन की बात को सुनने और कार्यक्रम से संबंधित फ़ोटो सरल ऐप पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने की अपील की है।

शायर डॉक्टर अख़लाक़ का दिल्ली मनाएगी जश्न

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

- उर्दू अकादमी दिल्ली की मदद से भारतीय महिला विकास समिति देहली मनाएगी
- अदब की रोशनी में जश्ने डॉक्टर अख़लाक़
- उनकी किताब 'संदल', 'मुट्ठी भर सूरज' मचा चुकी है धूम,
- जल्द ही ''ज़ख्मदान'' भी मंज़र-ए-आम पर आने वाला है

कुकरा खीरी। दशकों से शेरो शायरी के जरिए लोगों की धड़कन बने डॉ0 अख़लाक़ के सम्मान में दिल्ली में जश्ने डॉ0 अख़लाक़ मनाया जाएगा, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के शायर और तमाम बुद्धजीवी शामिल होंगे।

दिल्ली के नागलोई मेट्रो स्टेशन के निकट सुरभि स्टूडियो में होने वाले इस सम्मान समारोह के मौके पर ऑल इंडिया मुशायरा भी आयोजित किया गया है। अगर डॉ0 अख़लाक़ की बात करे तो उनका जन्म 1972 में यूपी के सीतापुर ज़िले के हरगांव क़स्बे के पास इस्माईलपुर में हुआ। उन्होंने सन 1995 में शायरी की दुनिया में क़दम रखा और वह शुरुआत से ही अपने शे'रों में जिद्दत की राह चुनी, जिससे उनकी शायरी ख़ास-ओ-आम में मक़बूल होने लगी। सन 2004 में उन्होंने लखीमपुर में सुकूनत अख़्तियार की अदबी सफ़र नशिस्तों,मुशायरों से शुरू होकर आकाशवाणी लखनऊ, दूरदर्शन लखनऊ और दूरदर्शन दिल्ली तक पहुंचा। उन्होंने न सिर्फ़ ग़ज़ल बल्कि नज़्म, क़तआत, नात पाक, हम्द, रूबाई और अफ़साना निगारी में भी अपने क़लम के जौहर दिखाए हैं।

उनका पहला शे'री मजमुआ ''संदल'' सन 2015 में फ़ख़रुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लखनऊ, की माली इमदाद से छपा सन 2023 में दूसरी किताब ''मुट्ठी भर सूरज'' को भी फ़ख़रुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी ने इमदाद दी।तीसरा मजमुआ ''ज़ख्मदान'' जल्द ही मंज़र-ए-आम पर आने वाला है।

30 नवंबर 2025 को उर्दू अकादमी दिल्ली की माली इमदाद से, भारतीय महिला विकास समिति देहली डॉक्टर अख़लाक़ का जश्न ''अदब की रोशनी में जश्ने डॉक्टर अख़लाक़'' उनवान से मनाने जा रही है, जिससे लखीमपुर की अदबी माहौल में खुशी की लहर है।

इस जश्न के मौक़े पर डॉक्टर ख़्वाजा सैयद हादी-उल-जीलानी ने कहा कि-ये ख़बर दिल को बेहद मसर्रत, इत्मीनान और सआदत का अहसास अता कर रही है कि डॉक्टर अख़लाक़ साहब की अदबी और इल्मी ख़िदमात के एतराफ़ में दिल्ली जैसे अज़ीम, जाज़िबे नज़र और अदबी शान रखने वाले शहर में निहायत पुर वक़ार और तारीख़ी नौइयत की तक़रीब ''जश्ने डॉक्टर अख़लाक़'' मुनक्क़िद की जा रही है। उन्होंने आगे कहा- डॉक्टर अख़लाक़ की शख़्सियत हमेशा से इल्मो फ़न की रोशनी, तहज़ीब-ओ-अख़लाक़ की खुशबू और खिदमते क़लम के खुलूस से पुर रही है। उन्होंने जिस मोहब्बत, सादगी और फ़िक्री इस्तक़ामत के साथ उर्दू अदब की ख़िदमत अंजाम दी है वो न सिर्फ अदबी हल्क़ों में आपको मुमताज़ बनाती है बल्कि नई नस्ल के लिए भी आपको एक रौशन मिसाल की हैसियत अता करती है।

एडीएम ने मितौली में परखी SIR की रफ्तार, टीम को दिया जोश भरने वाला मंत्र

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखीमपुर खीरी। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) की रफ्तार बढ़ाने के लिए प्रशासन अब मैदान में उतर आया है। शनिवार को डिप्टी डीईओ/एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह अचानक तहसील मितौली पहुँचे और वहाँ चल रहे एसआईआर कार्यों की बारीकी से पड़ताल की। बीएलओ द्वारा किए जा रहे गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन कार्य की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) मधुसूदन गुप्ता को जरूरी दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एडीएम ने न सिर्फ प्रगति रिपोर्ट देखी बल्कि पूरे स्टाफ से आमने-सामने बात कर काम की वास्तविक स्थिति जानी। उन्होंने टीम को सख्त लहजे में लेकिन प्रेरक अंदाज में साफ कहा कि जोश बनाए रखिए, काम की रफ्तार धीमी नहीं पड़नी चाहिए३ लक्ष्य समय पर हर हाल में पूरा होना चाहिए। मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने एडीएम के शब्दों से उत्साहित महसूस किया। निरीक्षण के दौरान एडीएम ने बीएलओ से एक-एक विवरण की जानकारी ली।

झांसी डीआरएम ने रेलवे स्टेशन कोंच का किया निरीक्षण, रेलवे कर्मचारियों दिए निर्देश

उरई। झांसी मंडल के डीआरएम अनुरुद्ध कुमार शनिवार को कोंच रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, यहां पर उन्होंने देश की सबसे छोटी ट्रेन और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते हुए रेलवे कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डीआरएम मंडल झांसी ने रेलवे स्टेशन पर सभी तकनीकी चीजों की बारीकी से जांच पड़ताल की और रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों को बारीकी से देखा। इस दौरान उन्होंने यात्रियों को आरक्षण को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश स्थानीय रेलवे अधिकारियों को दिए।डीआरएम ने नगर के व्यापारियों नेताओं और गणमान्य लोगों से मुलाकात भी की। इस दौरान तमाम स्थानीय लोगों और व्यापारियों एवं नेताओं ने रेल सेवा विस्तार और रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को लेकर डीआरएम को ज्ञापन दिया । डीआरएम ने देश की सबसे छोटी 14 किलोमीटर वाली ट्रेन का निरीक्षण किया और रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई समेत अन्य चीजों का बारीकी से निरीक्षण किया।

गौशालाओं में व्यवस्थाओं के निगरानी के लिए लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

बलरामपुर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में संचालित गौशालाओं की व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत करने के लिए अब सभी गौआश्रय स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यह निर्देश जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद के सभी गौआश्रय स्थलों पर रहने वाले गौवंशों की उचित देखभाल सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए हरा चारा, स्वच्छ पानी, चिकित्सा सुविधा, ठंड से बचाव तथा साफ-सफाई की स्थिति पूरी तरह सुव्यवस्थित और संतोषजनक होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि गौवंशों के लिए चारे की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी आश्रय स्थल पर चारे की कमी नहीं होनी चाहिए। पशुओं के लिए स्वच्छ पेयजल, फॉगिंग और नियमित सफाई की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने को कहा।

जिलाधिकारी ने कहा कि गौआश्रय स्थलों की निगरानी और पारदर्शिता के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जिससे व्यवस्थाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कैमरों की रिकॉर्डिंग नियमित रूप से चेक की जाए और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

बैठक में डीएम ने जनपद के सभी पशु चिकित्सालयों की स्थिति सुधारने पर जोर देते हुए कहा कि पशु चिकित्सक नियमित रूप से अस्पताल में उपस्थित रहें और मरीजों व पशुपालकों को समय से उपचार एवं परामर्श उपलब्ध कराएं। दवाइयों, टीकों और आवश्यक उपकरणों का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। यदि किसी स्थान पर कमी हो तो विभाग तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत करे। उन्होंने कहा कि गौआश्रय स्थलों का नियमित निरीक्षण किया जाए और निरीक्षण रिपोर्ट समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, पशुपालन एवं पंचायत विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

श्री विष्णु महायज्ञ के अंतिम दिवस पर विशाल भंडारे का आयोजन

मितौली खीरी। विकास खंड पसगवां के ग्राम खूँटी बुजुर्ग में श्री विष्णु महायज्ञ के अंतिम दिवस पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। श्री धाम वृंदावन से आए कलाकारों ने यज्ञ के विश्राम दिवस पर धनुष भंग लीला के दर्शन कराए। धनुष भंग लीला भगवान राम की एक प्रसिद्ध कथा है, जिसमें भगवान राम ने शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता जी का वरण किया था। इस लीला के माध्यम से कलाकारों ने भगवान राम की महानता और शक्ति का प्रदर्शन किया। साथ ही भंडारे का आयोजन यज्ञ के समापन के अवसर पर किया गया, जिसमें आसपास के गांवों से आए श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे गए, जिन्हें श्रद्धालुओं ने बड़े चाव से खाया।भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी शामिल थे। श्रद्धालुओं ने यज्ञ के समापन के अवसर पर भगवान की पूजा की और प्रसाद ग्रहण किया। श्री धाम वृंदावन से आए कलाकारों ने धनुष भंग लीला के माध्यम से भगवान राम की कथा को प्रस्तुत किया। कलाकारों की प्रस्तुति को देखकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। इस अवसर पर अध्यक्ष सुबोध दीक्षित, कोषाध्यक्ष भगवानदीन दीक्षित, महामंत्री लक्ष्मीकांत दीक्षित, विकास दीक्षित, राममोहन दीक्षित आदि उपस्थित रहे।

सुजानपुर गांव मे लगाया गया निशुल्क स्वास्थ्य कैप

गोला गोकर्णनाथ खीरी। शुक्रवार को सिंह हॉस्पिटल गोला नया बाईपास निकट रिलायंस पेट्रोल पंप के द्वारा निकटवर्ती गांव सुजानपुर में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें सैकड़ो मरीजों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर निशुल्क दवा का वितरण किया गया। इस दौरान डॉक्टर अमोल सिंह मैनेजिंग डायरेक्टर अर्पित सिंह फार्मासिस्ट हिमांशु वर्मा जीएनएम रिंकी, ऐएनएम मोनिका हॉस्पिटल संचालक बलवंत सिंह रेखा सहित तमाम ग्रामीण व मरीज मौजूद रहे।

अंतरजनपदीय गांजा तस्कर गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार

हमीरपुर। मौदहा पुलिस टीम ने शनिवार को कम्हरिया दरगाह के पास कम्हरियादूसायर रोड पर से अंतरजनपदीय तस्कर गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया हैं। इनके कब्जे से 4 किलो अवैध सूखा गांजा और सोने का हार बरामद हुआ है। कोतवाल संतोष सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपितों में हरियाणा के ग्राम देवली निवासी बदना पुत्र नीतू और फतेहपुर बिलोच निवासी सीमा हैं। दोनों लंबे समय से अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी और चोरी जैसी आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। पूछताछ में सीमा ने स्वीकारा कि पुलिस को बरामद हार उसने करीब चार दिन पहले बांदा बस स्टैंड के पास एक महिला के गले से चोरी किया था। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि आरोपित नीतू के खिलाफ दिल्ली में वर्ष 2021 का एक आपराधिक मुकदमा पहले से दर्ज हैं।

कफ सिरप की तस्करी पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने दिया सफाई, बताई राजनीति साजिश

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कोडीन कफ सिरप की तस्करी और अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद से प्रदेश भर में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इस प्रकरण में पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम बार-बार सामने आने के बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई है। शनिवार को धनंजय सिंह ने अपने फ़ेसबुक अकाउंट के माध्यम से एक संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी है कि कफ सिरप के मुद्दे पर उनके कुछ राजनीतिक विरोधियों ने पत्रकारों को गुमराह कर उनके बारे में भ्रम फैलाने का प्रयास किया है।

सीडीओ ने धान क्रय केंद्रों व सहकारी समितियों का किया औचक निरीक्षण

- धान खरीद से लेकर उर्वरक वितरण तक व्यवस्था पर कसा शिकंजा
- सीडीओ का फील्ड रिव्यू ड्राइव, कई कमियाँ पकड़ीं, अफसरों को फटकार

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखीमपुर खीरी। जिले में धान खरीद एवं उर्वरक वितरण व्यवस्था की स्थिति जानने के उद्देश्य से सीडीओ अभिषेक कुमार ने शनिवार को व्यापक सत्यापन अभियान संचालित कराया। उन्होंने जनपदीय अधिकारियों की टीम लगाकर जिलेभर के धान क्रय केंद्रों और सहकारी समितियों का फील्ड वेरिफिकेशन कराया। इसी क्रम में सीडीओ अभिषेक कुमार ने प्रशिक्षु आईएएस मनीषा धारवे के साथ कृषि उत्पादन मंडी समिति, राजापुर में स्थापित धान क्रय केंद्रों पर औचक पहुँचे। उन्होंने किसानों के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की जमीनी पड़ताल की और मौजूद किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएँ जानीं। निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने तौल मशीन व नमी मापक यंत्र की कार्यशीलता जांची। एक केंद्र पर डस्टर का मोटर खराब मिलने पर उन्होंने नाराज़गी जताते हुए उसे तुरंत ठीक कराने के निर्देश दिए। मंडी में मौजूद मितौली क्षेत्र से आए एक किसान से बातचीत के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मितौली क्रय केंद्र पर खरीद की गति धीमी है, जिसके कारण किसान मंडी में धान बेचने आया। इस पर सीडीओ ने मितौली क्रय केंद्र पर खरीद प्रक्रिया को तेज करने के स्पष्ट निर्देश दिए।

लखपेड़ागंज समिति में स्टॉक होते हुए भी वितरण ठप, सीडीओ नाराज़, लगाई फटकार

इसके बाद सीडीओ अभिषेक कुमार सीधे बी-पैक्स सहकारी समिति लखपेड़ागंज पहुंचे। यहां उन्होंने उर्वरक वितरण की वास्तविक स्थिति जानी और अभिलेखों की जांच की। निरीक्षण में पाया कि समिति पर उर्वरक का स्टॉक उपलब्ध है, लेकिन ई-पास मशीन में स्टॉक फीड न होने के कारण वितरण प्रभावित हो रहा है। इस पर सीडीओ ने सहायक आयुक्त एवं निबंधक (सहकारिता) को तत्काल निर्देशित किया कि ई-पास मशीन में स्टॉक की फीडिंग करवाकर उर्वरक का नियमानुसार समय से वितरण सुनिश्चित कराया जाए।

समय पर केंद्र खोलें, तेज करें तौल और 48 घंटे में भुगतान सुनिश्चित हो : सीडीओ

सीडीओ ने डिप्टी आरएमओ और एआरसीएस को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी धान क्रय केंद्र नियमित समय पर खुलें और अधिकारी स्वयं प्रतिदिन कम-से-कम पाँच केंद्रों का भ्रमण करें। सीडीओ ने तौल प्रक्रिया में आ रही सुस्ती पर भी सख्त रुख अपनाया। केंद्रों पर तौल बढ़ाने हेतु पर्याप्त कार्मिक लगाए जाएँ, ताकि तौल की गति बढ़ सके और किसानों को देरी न झेलनी पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि बैंकों से समन्वय कर 48 घंटे के भीतर किसानों का भुगतान हर हाल में सुनिश्चित कराया जाए।

टाटा विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का शेड्यूल घोषित

9 जनवरी से 5 फरवरी तक होंगे मुकाबले

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने टाटा विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। लीग का चौथा संस्करण 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक खेला जाएगा, जिसमें मुकाबले नवी मुंबई और वडोदरा में आयोजित किए जाएंगे। यह टूर्नामेंट एक बार फिर भारत और दुनियाभर की शीर्ष महिला क्रिकेटर्स के कौशल को प्रदर्शित करेगा।

सीजन की शुरुआत 9 जनवरी को नवी मुंबई में होने वाले धमाकेदार ओपनर से होगी, जहां मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस (एमआई) का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से होगा। नवी मुंबई में 9 से 17 जनवरी तक कुल 11 मैच खेले जाएंगे, जो टूर्नामेंट की रोमांचक शुरुआत तय करेंगे।

इसके बाद लीग का कारवां वडोदरा पहुंचेगा, जहां बाकी 11 मुकाबले सहित प्लेऑफ भी खेले जाएंगे। वडोदरा में पहला मुकाबला गुजरात जायंट्स और आरसीबी के बीच होगा, जिसके बाद 2025 फाइनलिस्ट दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) और मुंबई के बीच हाई-वोल्टेज भिड़ंत देखने को मिलेगी। लीग चरण 01 फरवरी तक चलेगा, जिसके बाद एक दिन का ब्रेक निर्धारित है।

एलिमिनेटर मुकाबला 3 फरवरी, मंगलवार को खेला जाएगा, जिसमें अंक तालिका में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें आमने-सामने होंगी। इसके विजेता को फाइनल में जगह पाने का मौका मिलेगा। अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली टीम सीधे 5 फरवरी 2026 को वडोदरा में होने वाले फाइनल में पहुंचेगी, जहां नए डब्ल्यूपीएल चैंपियन का ताज पहनाया जाएगा। हाल ही में नई दिल्ली में हुए मेगा ऑक्शन के बाद टीमों की संरचनाओं में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिससे डब्ल्यूपीएल 2026 अब तक का सबसे रोमांचक सीजन साबित होने की उम्मीद है। युवा भारतीय खिलाड़ियों और अनुभवी विदेशी सितारों के मिश्रण से यह टूर्नामेंट उच्च स्तरीय और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट

सुल्तान अज़लान शाह कप : भारत ने कनाडा को 14-3 से रौंदा, फाइनल में की जगह पक्की

एजेंसी

इपोह (मलेशिया)। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शनिवार को अपने आखिरी राउंड-रोबिन मुकाबले में कनाडा को 14-3 से करारी शिकस्त देकर सुल्तान अज़लान शाह कप 2025 के फाइनल में जगह सुनिश्चित कर ली।

भारत के डिफेंडर जुगराज सिंह टीम के शीर्ष स्कोरर रहे, जिन्होंने कुल चार गोल दागे–तीन पेनल्टी कॉर्नर और एक पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए। इसके अलावा अभिषेक, अमित रोहिदास और राजिंदर सिंह ने दो-दो गोल किए। वहीं सेल्वम कार्ती, निलकांत शर्मा, संजय और दिलप्रीत सिंह ने एक-एक गोल का योगदान दिया।

इस शानदार जीत के साथ भारत ने अंक तालिका में शीर्ष दो में अपनी जगह पक्की कर ली है, चाहे दिन में

बाद के मुकाबलों के परिणाम कुछ भी हों। क्रेग फुल्टन की कोचिंग में खेल रही भारतीय टीम का सामना फाइनल में संभवतः बेल्जियम से होगा–वही टीम जिसने राउंड-रोबिन चरण में भारत को एकमात्र हार दी थी।

फिलहाल बेल्जियम 10 अंकों के साथ मजबूत स्थिति में है और शनिवार को बाद में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा, जिसके सात अंक हैं। न्यूजीलैंड के पास फाइनल में पहुंचने की मामूली उम्मीद है, लेकिन इसके लिए उसे कम से कम छह गोल के अंतर से जीत दर्ज करनी होगी।

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बाद तैराक श्रीहरि नटराज की नजरें 2026 एशियन गेम्स पर

एजेंसी

जयपुर। टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके तैराक श्रीहरि नटराज ने चल रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (केआइयूजी) राजस्थान 2025 में अपने शानदार प्रदर्शन से एक बार फिर सुर्खियां बटोरीं। जैन यूनिवर्सिटी की ओर से हिस्सा लेते हुए उन्होंने कुल 11 पदक जीते, जिसमें 9 स्वर्ण और 2 रजत शामिल हैं।

24 वर्षीय नटराज ने स्वीकार किया कि वे अपने श्रेष्ठ टाइमिंग के करीब भी नहीं थे, क्योंकि यह उनका ऑफ-सीजन चल रहा है। हाल ही में अहमदाबाद में हुए एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप में सात पदक जीतने के बाद वे पूर्ण रूप से उच्च स्तरीय प्रशिक्षण में नहीं थे, लेकिन फिर भी प्रतियोगिता में काफी आगे रहे और अपनी यूनिवर्सिटी को तैराकी में 45 पदकों (27 स्वर्ण सहित) की बड़ी उपलब्धि दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

नटराज अब जापान में होने वाले 2026 एशियन गेम्स और ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ल्लएशियन गेम्स में मैं 25 साल का हो जाऊंगा और यही उम्र तैराकों के लिए पीक होती है। अब मैं अपने गेम और शरीर को बेहतर समझता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं वहां पदक जीत सकता हूं। श्रीहरि को उम्मीद है कि एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप में मिले सात पदकों के आधार पर उन्हें टार्गेट एशियन गेम्स ग्रुप में जगह मिलेगी। उन्होंने कहा, ल्ल2018 के पहले खेलो इंडिया गेम्स के बाद मुझे टॉप्स में शामिल किया गया था और

एशिया कप इंडिया-19 में सिरसा के कनिष्क चौहान का चयन

सिरसा। आगामी 12 दिसंबर से दुबई में आरंभ होने वाले अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप में भारतीय टीम में सिरसा के कनिष्क चौहान के चयन पर सिरसा का प्रत्येक खेल प्रेमी फूला नहीं समा रहा है। सिरसा क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव डॉ. वेद बेनीवाल व कनिष्क के प्रशिक्षक जसकरण सिंह ने शनिवार को बताया कि हरियाणा क्रिकेट 19 के कप्तान रह चुके कनिष्क चौहान अब से पूर्व अंडर-19 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया व इंग्लेंड में भी अपनी शानदार प्रतिभा का परिचय दे चुके हैं। अब एक बार फिर कनिष्क चौहान गेंद व बल्ले से दुबई में भारत की शान बढ़ाने के लिए जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं। पुरुष अंडर-19 एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व आयुष म्हात्रे करेंगे।डॉ.बेनीवाल व जसकरण सिंह ने कहा कि कनिष्क चौहान की प्रतिभा व एसोसिएशन द्वारा उचित मंच प्रदान किए जाने का ही परिणाम है कि आज सिरसा का छोरा अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप में भारत के लिए पसीना बहाएगा

यूईएफए महिला नेशंस लीग – फाइनल के पहले चरण में जर्मनी और स्पेन का मुकाबला ड्रॉ

एजेंसी

कैसरस्लॉटर्न। मौजूदा विश्व चैंपियन स्पेन ने गोलकीपर काता कॉल के शानदार प्रदर्शन की बदौलत शुक्रवार को यूईएफए महिला नेशंस लीग फाइनल के पहले चरण में जर्मनी को गोलरहित ड्रॉ पर रोके रखा। अब खिताब का फैसला मंगलवार को मैड्रिड में होने वाले दूसरे चरण में होगा। मैच के दौरान जर्मनी ने गेंद पर नियंत्रण और आक्रामकता दोनों में बढ़त बनाए रखी, जबकि स्पेन ने गहरी रक्षात्मक रणनीति अपनाते हुए मैच को ड्रॉ की दिशा में मोड़ने की कोशिश की। जर्मन खिलाड़ियों ने कई मौकों पर गोल के करीब पहुंचकर भी मौका गंवा दिया।

जर्मनी की स्टार स्ट्राइकर क्लारा ब्यूहल, जिन्हें पहले हाफ में चार साफ मौके मिले, ने ज़ेडडीएफ से कहा, ल्लहमने बेहद साहसी खेल दिखाया।

गोल न कर पाने का मलाल है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन टीम का आत्मविश्वास बढ़ाता है और अब वे मैड्रिड में होने वाले निर्णायक मुकाबले को लेकर उत्साहित हैं।

जर्मन कोच क्रिशचियन वुक ने टीम की तारीफ करते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने साबित किया कि वे स्पेन जैसी मजबूत टीम के खिलाफ न सिर्फ टिक सकते हैं, बल्कि अपना खेल भी खेल सकते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि कई मौकों के बावजूद गोल न कर पाना निराशाजनक रहा।

मैच से पहले जर्मनी ने स्पेन से यूरो 2025 के सेमीफाइनल में मिली हार का बदला लेने की बात कही थी, लेकिन स्पेन ने उनकी हर कोशिश को नाकाम किया। हालांकि, स्पेन की कोच सोनिया बर्मुडेज़ ने कहा था कि उनकी टीम ड्रॉ के लिए नहीं खेलेगी, पर मैदान पर खेल उनकी बात के उलट दिखाई दिया।पहले हाफ में फ्रांज़िस्का केट का शॉट रोकने के लिए काता कॉल ने बेहद अहम सेव किया। इसके तुरंत बाद जूल ब्रांड का प्रयास आयरीन पार्डे स ने गोल लाइन पर रोक लिया।

दूसरे हाफ में स्पेन के लिए एस्तेर गोंज़ालेज़ ने 52वें मिनट में पोस्ट पर गेंद मारी, जो उनकी सबसे बड़ी कोशिश रही। वहीं 71वें मिनट में ब्यूहल का शॉट भी पोस्ट से टकरा गया।अंतिम मिनटों में जर्मनी को जीत का मौका मिला था, जब जूल ब्रांड ने गेंद स्योके नुस्केन तक पहुंचाई, लेकिन काता कॉल ने बाहर आकर खतरा टाल दिया। अब दोनों टीमों के बीच मंगलवार को मैड्रिड में होने वाला दूसरा चरण खिताब का असली फैसला करेगा।

सिक्सर्स ने लेफ्ट-आर्म तेज गेंदबाज़ लॉरेन चीटल के साथ करार दो साल बढ़ाया

एजेंसी

सिडनी। सिडनी सिक्सर्स ने अपनी तेज गेंदबाज़ी इकाई को मज़बूती देने के लिए अपनी प्रमुख लेफ्ट-आर्म क्विक लॉरेन चीटल का करार कम से कम दो और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। चीटल का पिछला कॉन्ट्रैक्ट मौजूदा सत्र के अंत तक था, लेकिन अब वह महिला बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) 13 तक टीम के साथ जुड़ी रहेंगी। चीटल पिछले नौ वर्षों से सिक्सर्स का हिस्सा हैं। वह 2017 में सिडनी थंडर से इस टीम में शामिल हुई थीं, जहां उन्होंने अपने पहले दो सत्र बिताए थे। चीटल ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कहा, ल्लसिक्सर्स मेरे करियर का बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं और अगले दो सत्रों के लिए टीम के साथ बने रहने पर मुझे गर्व है। मैं टीम की क्षमता पर भरोसा करती हूं और मैजेंटा जर्सी के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं।27 वर्षीय चीटल डब्ल्यूबीबीएल में 100 विकेट के आंकड़े के करीब हैं। अब तक वे 93 मैचों में 95 विकेट ले चुकी हैं। सिक्सर्स के वर्तमान खिलाड़ियों में वह कप्तान एश्ले गार्डनर के बाद दूसरे स्थान पर हैं और टीम की सबसे सफल तेज गेंदबाज़ हैं। कम उम्र के बावजूद चीटल का अंतरराष्ट्रीय अनुभव काफी समृद्ध है। उन्होंने 17 साल की उम्र में 2016 में ऑस्ट्रेलिया के लिए पदार्पण किया था और उसी वर्ष टी20 विश्व कप में भी हिस्सा लिया था। वह तीनों प्रारूपों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुकी हैं। इस सीजन कप्तानी में बदलाव के बीच सिक्सर्स के लिए चीटल का यह नया करार नेतृत्व के लिहाज़ से भी महत्वपूर्ण है। कंधे और पीठ की चोटों के अलावा दो बार त्वचा कैंसर का सामना करने के बावजूद चीटल ने हमेशा मजबूती से वापसी की है और कठिन परिस्थितियों में जूझने के लिए जानी जाती हैं।

आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर 91 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बैंकिंग विनियमन कानून के कुछ नियमों का उल्लंघन करने के मामले में निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक पर 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना निजी क्षेत्र के इस बैंक पर 'अपने ग्राहक को जानो' (केवाईसी) से जुड़ी कानूनी और नियामकीय बाध्यताओं में कमियों के लिए लगाया गया है। आरबीआई ने जारी एक बयान में कहा कि एचडीएफसी बैंक पर ये जुर्माना बैंक पर बैंकिंग विनियमन कानून के कुछ नियमों का उल्लंघन, कर्ज पर ब्याज दर से जुड़ी शर्तों का पालन न करने, वित्तीय सेवाओं के लिए जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता के दिशानिर्देशों तथा केवाईसी से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने के कारण लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने बताया कि 31 मार्च, 2024 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के अनुसार बैंक का निगरानी मूल्यांकन करने के लिए एक सांविधिक जांच की गई थी।

सरकारी सुधारों, विनिर्माण प्रोत्साहन से दूसरी तिमाही की जीडीपी वृद्धि दर 8.2 फीसदी हुई

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों और सुधारों की वजह से चालू वित्त वर्ष 2025-26 की (जुलाई-सितंबर) दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था ने 8.2 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है।

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर गुजरात के वडोदरा में आयोजित एक नेशनल पदयात्रा में हिस्सा लेते हुए जीडीपी पर पूछे गए सवाल के जवाब में पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता के बावजूद देश का निर्यात भी अच्छी वृद्धि दर्ज कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने बिजनेस को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं और सुधार किए

हैं, जिससे मौजूदा वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में अर्थव्यवस्था को 8.2 फीसदी की ग्रोथ हासिल करने में मदद मिली है।

उन्होंने कहा कि व्यापार के मोर्चे पर ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद देश का निर्यात भी अच्छी ग्रोथ दर्ज कर रहा है। उन्होंने कहा कि 8.2 फीसदी की ग्रोथ सरकार द्वारा उठाए गए कई सुधार उपायों को दिखाती है। गोयल ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और कारोबार को आसान बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने 'एक्स' पर लिखा कि आज वडोदरा में श्रम रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया एवं मंत्री वीरेंद्र कुमार के साथ सरदार पटेल की 150वीं जन्मजयंती पर आयोजित यूनिटी मार्च (पदयात्रा) में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। वडोदरा में कदम रखते ही सरदार पटेल की विरासत का गर्व महसूस होता है। उनकी दृढ़ता से अनेक रियासतें मिलकर एक भारत बनीं। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वही संकल्प हमें आत्मनिर्भर और विकसित भारत की राह दिखा रहा है।

संक्षिप्त समाचार

बीसीसीआई विजय मर्चेंट ट्रॉफी : हिमाचल की अंडर-16 मेन टीम का चयन

धर्मशाला। बीसीसीआई विजय मर्चेंट ट्रॉफी 2025 के लिए हिमाचल की मेन टीम का चयन कर लिया गया है। हिमाचल की टीम प्रतियोगिता में अपना पहला मैच सौराष्ट्र के साथ खेलेगा। यह मैच 7 से 9 दिसम्बर तक विजयवाड़ा में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मैच 12 से 14 दिसंबर तक हरियाणा के साथ, 18 से 20 दिसम्बर तक दिल्ली के साथ, 23 से 26 दिसम्बर तक महाराष्ट्र और 29 से 31 दिसंबर तक हैदराबाद के साथ होगा। सभी मैच विजयवाड़ा में ही खेले जाएंगे। उधर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) ने इस टीम का चयन हैदराबाद और विजयवाड़ा में पुरुष अंडर-16 अभ्यास मैच और बीसीसीआई विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए एक साथ किया है। अंडर-16 पुरुष टीम की कमान कांगड़ा के आदिल राणा को सौंपी गई है। इसके अलावा अभय चंदेल बिलासपुर, अखिलेश गौतम बिलासपुर, प्रिंस सुरिंदर ठाकुर बिलासपुर, अक्षित ठाकुर चंबा, कनिष्क शर्मा हमीरपुर, साहिल कुमार हमीरपुर, तनीश कुमार कांगड़ा, वेदांत शर्मा कुल्लू, आदिश मिन्हास मंडी, अथर्व आर्य शिमला, हार्दिक शर्मा सिरमौर, आर्यन मेहता सोलन, समीर सोलन, उत्तम परमार सोलन, भविष्य भारद्वाज ऊना, सुमित संधू ऊना, वैभव शर्मा ऊना को टीम में शामिल किया गया है। वहीं अजय मोहन शर्मा कोच, तरूण कुमार शर्मा सहायक कोच, गुलशन चौधरी फील्डिंग कोच, अमृत शर्मा फिजियो, शुभम कथूरिया ट्रेनर, संदीप भास्कर वीडियो विश्लेषक, रवि कांत पार्श्व भुजा तथा मुकेश शर्मा को प्रबंधक का जिम्मा सौंपा गया है।

एसुस जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंज्यूमर नोटबुक कंपनी रही

नई दिल्ली। ताइवान की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनी एसुस इंडिया ने वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए भारत में कंज्यूमर नोटबुक कंपनी के रूप में दूसरा स्थान हासिल कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। आईडीसी क्वार्टरली पर्सनल कम्प्यूटिंग डिवाइस ट्रैकर, 2025 क्यू3 की रैंकिंग में उसने यह उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इस बात से स्पष्ट है कि एसुस हर साल उल्लेखनीय वृद्धि कर रहा है। यह वृद्धि ब्रांड के प्रति ग्राहकों के भरोसे को बनाये रखने, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के विस्तार और देश के 600 से अधिक जिलों में खुदरा टचपॉइंट्स बढ़ाने के प्रयासों का परिणाम है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि एसुस इंडिया ने एसुस एआई पीसी, कंज्यूमर और गेमिंग नोटबुक्स के साथ-साथ एआईओ, डेस्कटॉप और एक्सेसरीज़ श्रेणियों में महत्वपूर्ण नवाचार पेश किये हैं। इस साल कंपनी ने मल्टी-कलर विवोबुक, आरओजी एली एक्स और कई सफल अभियानों की शुरुआत की जो काफी लोकप्रिय हुए। एआईओ सेग्मेंट में भी इसने बाजार में दबदबा बनाये रखा और प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पाद में शामिल रहा। एसुस इंडिया ने सबसे हल्का कोपायलट प्लस पीसी, आरओजी एली ज़ेनबुक ए14 लॉन्च किया और भारत में एनवीडिया आरटीएक्स 5000 सीरीज़ में नंबर एक बाजार हिस्सेदारी हासिल की। एसुस इंडिया के उपाध्यक्ष अर्नोल्ड सू ने कहा कि साल 2025 की शुरुआत से ही कंपनी भारत में खुद को ऐसे पीसी ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है जो टेक्नोलॉजी के जरिये ग्राहकों के लिए सुविधा लाये। उन्होंने बताया कि कंपनी ने कंज्यूमर नोटबुक पीसी श्रेणी में सालाना सात प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है और अब इस श्रेणी में दूसरे स्थान पर है।

अक्टूबर में हवाई यात्रा की मांग 6.6 प्रतिशत बढ़ी

एजेंसी

नयी दिल्ली। वैश्विक स्तर पर अक्टूबर में हवाई यात्रा की मांग में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मांग 8.5 प्रतिशत और घरेलू यात्रा की मांग 3.4 प्रतिशत बढ़ी है।

हवाई यात्रा की मांग को राजस्व यात्री किलोमीटर के रूप में मापा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आयटा) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में 2024 के मुकाबले अक्टूबर 2025 में कुल मांग 6.6 प्रतिशत बढ़ी है। वहीं, कुल क्षमता (उपलब्ध सीट किलोमीटर) 5.8 प्रतिशत और लोड फैक्टर (भरी सीटों का अनुपात) 84.6 प्रतिशत पर पहुंच गया जो एक साल पहले के मुकाबले 0.7 प्रतिशत

अधिक है।

विमान सेवा कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए क्षमता में 7.1 प्रतिशत की और घरेलू यात्रा के लिए 3.6 प्रतिशत की वृद्धि की। आयटा के महानिदेशक विली वॉल्श ने कहा कि अक्टूबर के महीने में अच्छा प्रदर्शन रहा। कई महीने के सपाट प्रदर्शन के बाद उत्तरी अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय यातायात में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि साल के अंतिम दो महीने के लिए ट्रेंड उत्साहजनक है। शिड्यूल के अनुसार नवंबर में सीट क्षमता 3.6 प्रतिशत और दिसंबर में 4.7 प्रतिशत बढ़ेगी।

जारी आंकड़ों के अनुसार तीसरी तिमाही में पश्चिम एशिया में हवाई यात्रा की मांग सबसे अधिक 10.5 प्रतिशत बढ़ी। अफ्रीका में इसमें 8.8 फीसदी, एशिया प्रशांत क्षेत्र में 8.1 फीसदी, यूरोप में 6.7 फीसदी, लातिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों में 6.1 प्रतिशत और उत्तरी अमेरिका में 2.5 प्रतिशत बढ़ी है। आयटा ने अक्टूबर के हवाई माल परिवहन के भी आंकड़े जारी किये हैं। माल परिवहन की मांग, जिसे कार्गो टन-किलोमीटर के रूप में मापा जाता है, अक्टूबर में 4.1 प्रतिशत बढ़ी। यह लगातार आठवां महीना है जब इसमें वृद्धि दर्ज की गयी है।

चावल, गेहूं नरम; चीनी मजबूत; दालों, खाद्य तेलों में घट-बढ़

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू थोक जिंस बाजारों में शनिवार को चावल की औसत कीमतों में नरमी रही। गेहूं के दाम भी घट गये। चीनी में तेजी रही जबकि खाद्य तेलों और दालों में उतार-चढ़ाव देखा गया।

औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत 21 रुपये टूटकर 3,822.15 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गयी। गेहूं भी 14 रुपये की गिरावट के साथ 2,838.46 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। आटे की कीमत चार रुपये बढ़ी।

दाल-दलहनों में उड़द दाल 14 रुपये प्रति क्विंटल मजबूत हुई। तुअर दाल 60 रुपये और मसूर दाल 53

रुपये प्रति क्विंटल उतर गयी। चना दाल 32 रुपये और मूंग दाल चार रुपये प्रति क्विंटल सस्ती हुई।

स्थानीय बाजारों में मूंगफली तेल औसतन 159 रुपये प्रति क्विंटल फिसल गया। सरसों तेल की कीमत 39 रुपये और पाम ऑयल की 21 प्रति क्विंटल टूट गयी। वनस्पति 20 रुपये और सोया तेल 11 रुपये प्रति क्विंटल सस्ता हुआ जबकि सूरजमुखी तेल चार रुपये महंगा हुआ।

स्वामी मुद्रक प्रकाशक एवं सम्पादक हरिनाथ सिंह * द्वारा टिनटिन प्रिन्टेक प्राइवेट लिमिटेड डी-33 अमौसी इण्डस्ट्रीयल एरिया, नादरगंज, लखनऊ से मुद्रित एवं 1/39 प्रथम तल करामत मार्केट निशातगंज, लखनऊ से प्रकाशित, सम्पर्क-522-4064242

Email: noidarp@gmail.com, therptimes@yahoo.com, 9918735329 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.पी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।

सूचना

पाठकों को सुझाव दिया जाता है, कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों पर कार्यवाही करने से पहले स्वयं उचित जाँच-पड़ताल कर लें। समाचार पत्र या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद या सेवा हेतु किये गये किसी दावें की सच्चाई का आश्वासन नहीं देता तथा ऐसे विज्ञापनों पर विश्वास करके किसी भी व्यक्ति को हुई क्षति, हानि, परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

अवैध हथियार बेचने वाले पांच गिरफ्तार

भारी मात्रा में पिस्टल और देसी तमंचा बरामद

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

नोएडा। थाना दनकौर पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद- फरोख्त करने वाले पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने तीन पिस्टल ,तीन देसी तमंचा, तथा 50 हजार रुपए नगद और घटना में प्रयुक्त होने वाली दो कार बरामद किया है। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि आरोपी काफी दिनों से अवैध रूप से हथियार के खरीद फरोख्त में संलिपित हैं।

अपर पुलिस उपयुक्त जोन तृतीय सुधीर कुमार ने बताया कि बीती रात को थाना दनकौर पुलिस को सूचना मिली कि काले रंग की एक स्कॉर्पियो कार तथा नीले रंग की एक बलेनो कार में सवार कुछ लोग अवैध रूप से हथियार बेचने के लिए ग्रेटर नोएडा में आए हैं। उन्होंने बताया कि

सूचना के आधार पर पुलिस ने चेकिंग शुरू की तथा बुढ़िया गोल चक्कर के पास से पुलिस ने काले रंग की स्कॉर्पियो और बलेनो कार को चेकिंग के दौरान अपने कब्जे में लिया। उन्होंने बताया कि कार में सवार गजेंद्र उर्फ गज्जू पुत्र हरवीर निवासी दादरी ,सुमित कुमार उर्फ गुंडा निवासी कासना, सागर भाटी पुत्र श्यामवीर निवासी ग्राम कमबख्तपुर ग्रेटर नोएडा, हर्ष सिंघल पुत्र सूरज सिंघल निवासी दनकौर तथा निखिल भाटी पुत्र श्यामवीर निवासी बीटा- 2 को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इनके पास से पुलिस ने तीन पिस्टल 32 बोर ,160 कारतूस, तीन देसी तमंचा 315 बोर ,6 कारतूस तथा 50 हजार रुपए नगद बरामद किया है।

उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार बदमाशों ने पुलिस को बताया कि वे लोग काफी दिनों से अवैध रूप से हथियार खरीदने बेचने के धंधे में संलिप्त है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि ये लोग असलहा और कारतूस मथुरा के जय गुरुदेव मंदिर के पीछे रहने वाले बंटू से खरीदते हैं। बंटू इन्हें महाकाली आर्म्स एंड एमूलेशन की दुकान जोकि मथुरा में है वहां से कारतूस सस्ते दाम पर खरीद कर उपलब्ध करवाता है। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि अवैध हथियार बेचकर जो रकम ये लोग कमाते हैं उससे मौज मस्ती करते हैं। इनके पास से जो रकम बरामद हुई है वह अवैध हथियार और कारतूस बेचकर कमाए गए मुनाफ़े की है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि आरोपी काफी दिनों से अवैध रूप से हथियार की खरीद- फरोख्त में संलिप्त हैं। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये बदमाश कुख्यात बदमाशों को अवैध हथियार सप्लाई तो नहीं करते हैं। पुलिस को इनसे पूछताछ के दौरान कई अहम सुराग मिले हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई कर रही है।

पल्स पोलियो अभियान को लेकर कालपी में जुटी टास्क फोर्स, एसडीएम ने दिए निर्देश

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

उरई। जिले की कालपी तहसील में आगामी पल्स पोलियो अभियान की सफलता के लिए शनिवार को तहसील स्तरीय टास्क फोर्स बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता कालपी के एसडीएम मनोज कुमार सिंह ने की और इसमें स्वास्थ्य, बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा आपूर्ति विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 14 दिसंबर से शुरू होने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की तैयारियों की समीक्षा करना और सभी संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था। एसडीएम मनोज कुमार सिंह ने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अभियान को लेकर कड़े निर्देश जारी किए। बैठक के दौरान तहसील के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए जाने वाले पोलियो बूथों को सुचारू रूप से चलाने के सभी इंतजाम पूरे करने के निर्देश दिए गए। यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि प्रत्येक बूथ पर पर्याप्त मात्रा में पोलियो की दवा, कोल्ड चेन का उचित प्रबंधन और कार्यरत कर्मी मौजूद हों।

एसडीएम ने जोर देकर कहा कि अभियान के दौरान तहसील के 5 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे तक पोलियो की दवा पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि केवल टीम वर्क के दम से ही इस अभियान को 100 प्रतिशत सफल बनाया जा सकता है। एसडीएम मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि पोलियो एक गंभीर बीमारी है, लेकिन टीकाकरण के जरिए इसे पूरी तरह से रोका जा सकता है। हमारा लक्ष्य है कि कालपी तहसील का कोई भी बच्चा इस टीके से वंचित न रहे। इसके लिए हमने सभी विभागों को पुख्ता तैयारी करने के निर्देश दिए हैं।

निषाद राज बोट सब्सिडी योजना में प्रयागराज के सौ से अधिक मछुआरों को मिलेगा लाभ

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री डॉ. संजय निषाद के प्रयास से प्रयागराज के मछुआरों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। इस वित्तीय वर्ष में शत प्रतिशत निषाद राज बोट सब्सिडी योजना का लाभ यागराज के मछुआरों को दिया जाएगा। यह जानकारी मत्स्य विकास अधिकारी कोरांव परिक्षेत्र मनोज कुमार ने दी।उन्होंने बताया कि केन्द्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार लगातार मछुआरा समाज एवं मछली पालन के कारोबार से जुड़े परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा संचालित निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में प्रयागराज जिले के सौ से अधिक मछली करोबार से जुड़े लोगों ने बोट सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है।

अब अतिक्रमण गैंग जोनवार होगा संचालित, पॉच गैंग का होगा गठन

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर निगम ने अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए अभियान शुरू किया है। इसके लिए कुल पॉच टीमें बनाई जा रही हैं । जिसका संचालन जोनल अधिकारी करेंगे। अभियान जोनल अधिकारी के नेतृत्व में उसी जोन में चलेगा। अभी तक नगर निगम मुख्यालय से अतिक्रमण अभियान चलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। यह जानकारी नगर निगम के जनसम्पर्क कार्यालय ने दी। शनिवार को बताया गया कि प्रत्येक गैंग में 5 कार्मिक होगें। चार जोनों के लिये 4 टीमें तथा 1 टीम नगर निगम मुख्यालय में तैनात होगा। नगर निगम सीमा विस्तार हो जाने के कारण अतिक्रमण की शिकायतें अधिक संख्या में प्राप्त हो रही है, उसी के दृष्टिगत नगर निगम प्रशासन ने विगत 26 नवम्बर को कार्यकारिणी में इसके लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे कार्यकारिणी समिति ने स्वीकृति प्रदान की थी। इस टीम के द्वारा जमीन की पैमाईश भी होती है। जोनल अधिकारी के साथ अतिक्रमण टीम स्वच्छता अभियान चलाती है। वी0आई0पी0 आगमन के साथ शहर में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते व्यवस्था बनाने में आसानी रहेगी। इसके अलावा अतिक्रमण अभियान, प्रतिबंधित प्लास्टिक अभियान, आई0जी0आर0एस0 का निस्तारण , गुणवत्तापूर्वक कार्यवाही में भी आसानी रहेगी।

मानसिक तनाव के चलते महिला ने की आत्महत्या

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोयडा में थाना सेक्टर 20 क्षेत्र के निठारी गांव में रहने वाली एक 31 वर्षीय विवाहिता ने बीती रात को मानसिक तनाव के चलते अपने घर पर पंखे के कुंडे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली । मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है।

थाना सेक्टर 20 के प्रभारी निरीक्षक डीपी शुक्ल ने बताया कि श्रीमती आशा पत्नी हरीकिशोर सिंह उम्र 31 वर्ष निठारी गांव में विजेंद्र अवाना के मकान में किराए पर रहती थी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की रात को आशा ने अपने घर पर पंखे के कुंडे से चुन्नी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली । उन्होंने बताया कि मृतका के भाई ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि महिला की 13 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस मृतका के परिवार के लोगों से पूछताछ कर आत्महत्या के कारण का पता लग रही है। उन्होंने बताया कि अगर मृतका के परिजन इस मामले में कोई शिकायत करेंगे तो पुलिस मामले की जांच करेगी।

संपादक मण्डल

संस्थापक/संरक्षक
संजीव श्रीवास्तव

प्रधान संपादक
हरिनाथ सिंह

सलाहकार संपादक
डॉ एमएए खान आईएएस (रि)
डॉ ओम प्रकाश आईएएस (रि)
आशुतोष रंजन
अनिल तिवारी
आर पी शुक्ल आईएएस (रि)
मेजर के किशोर
हरीशंकर शुक्ल पीपीएस (रि)

स्थानीय संपादक
दिनेश कुमार गर्ग

संपादक समन्वय
अभयानंद शुक्ल

आध्यात्मिक संपादक
राम महेश मिश्र

ब्यूरो चीफ
पीयूष त्रिपाठी

स्टेट कोआर्डिनेटर
विपिन सोनी

संपर्क मुख्यालय
कार्यालय फोन नं.: 0522-4643988
www.rashtriyaprastavana.com
ई-मेल: noidarp@gmail.com

संपर्क कार्यालय
प्रधान कार्यालयः 1/39, प्रथम तल करामत मार्केट, निशातगंज, लखनऊ
प्रशासनिक कार्यालयः 61 ए, मानस नगर, जियामऊ, हज़रतगंज, लखनऊ

27 पंचायत सहायकों की एसआईआर कार्य में लापरवाही बरतने पर सेवा समाप्त

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

महोबा। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य (एसआईआर) में लापरवाही बरतने वालों पर प्रशासन सख्त एक्शन लिया है। जहां ग्राम पंचायत स्तर पर चल रहे एसआईआर काम में रुचि न लेने पर जनपद के चारों ब्लाकों में 27 पंचायत सहायकों की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश डीपीआरओ ने एडीओ पंचायत को दिए हैं। जिला पंचायती राज अधिकारी चंद्रकिशोर वर्मा ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण विकास विभाग की ऑनलाइन मीटिंग में सीडीओ बलराम कुमार ने सभी ब्लॉकस्तरीय अधिकारियों और पंचायत सचिवों को एसआईआर से संबंधित जिम्मेदारियां सौंपी हैं। एसआईआर कार्य में सहयोग के लिए बीएलओ की सहायता के लिए पंचायत सहायकों को बूथ पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं । सीडीओ के निर्देश पर पंचायत सहायकों की उपस्थिति के बारे में जानकारी लेने पर जिलेभर के 27 पंचायत सहायक कार्यस्थल से अनुपस्थित पाए गए। जिनमें चरखारी ब्लॉक की चार ग्राम पंचायतों ,कबरई और जैतपुर ब्लॉक की छह-छह ग्राम पंचायतों, व पनवाड़ी ब्लॉक की 11 ग्राम पंचायतों के पंचायत सहायकों की सेवा समाप्ति के प्रस्ताव एडीओ पंचायत को तीन दिनों में ग्राम पंचायत स्तर पर भेजने के आदेश दिए गए हैं।प्रशासन के कड़े रुख से गहन पुनरीक्षण कार्य में लगे अन्य कर्मियों में हड़कंप मच गया है। जिले भर में मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण कार्य में लगाए गए बूथ लेबल ऑफिसर (बीएलओ) के सहयोग के लिए ग्राम प्रधान, कोटेदार,पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत सचिव, समेत सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। पर्यवेक्षण के लिए एसडीएम व तहसीलदारों को तैनात किया गया है। इसके बाद भी अभी तक जिले में केवल 50 फीसदी डाटा ही ऑनलाइन हो सका है।एसआईआर कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में कबरई ब्लॉक की ग्राम पंचायत , डिगरिया, श्रीनगर, सिचौरा, सिजहरी, ढिकवाहा और कबरई देहात के पंचायत सहायकों पर कार्रवाई होगी। जबकि पनवाड़ी ब्लॉक की ग्राम पंचायत अमानपुरा, विजयपुर, पनवाड़ी, नकरा, कोहनिया, किल्हौआ, काशीपुरा, तेईया, चौका, सौरा व बम्हौरीकुर्मिन के पंचायत सहायक ,चरखारी ब्लॉक की ग्राम पंचायत अक्ठौहा, कुड़ार, बमरारा व गौरहारी, जैतपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत गुढ़ा, जैलवारा, कमालपुरा, बिहार, थुरट और सलैयामाफ, के पंचायत सहायक शामिल हैं।

पशुपालकों को बंधक बनाकर हथियारबंद बदमाश 48 भेड़ लेकर फरार

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

मीरजापुर। उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जनपद में संतनगर थाना क्षेत्र के पड़रिया काला गांव के कुसियारिया मजरे में शुक्रवार देर रात अज्ञात हथियारबंद चोरों ने पशुपालकों को बंधक बनाकर 48 से अधिक भेड़ चोरी कर ले गए। आधी रात हुई इस घटना की सूचना पर पहुंची थाना

पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कुसियारिया निवासी शिवनाथ पाल पुत्र दर्शू पाल और शिवबलि पाल पुत्र महावीर पाल पशुपालक हैं। दोनों बीती रात शुक्रवार को अपनी भेड़ों के पास मढ़हा लगाकर सो रहे थे। रात लगभग दो बजे एक वाहन से पहुंचे आधा दर्जन बदमाश जाली के भीतर बंधी भेड़ों को वाहन पर लादने लगे। विरोध करने पर बदमाशों ने असलहा दिखाते हुए दोनों पशुपालकों को चारपाई से बांध दिया और सभी भेड़ों को उठाकर फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद पीड़ितों ने शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्हें बंधन से मुक्त कराया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले दो हफ्तों से क्षेत्र में भेड़ चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे ग्रामीण भयभीत हैं और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। सूचना पर थानाध्यक्ष संतनगर राजेश कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे। उन्होंने बताया कि मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और जल्द ही भेड़ चोरी और ऐसा करने वालों का पर्दाफाश किया जाएगा।

101 निर्धन एवं गरीब बेटियों के पिता बने राजेश

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

अमेठी। प्रसिद्ध उद्योगपति एवं अमेठी जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रहरि उर्फ राजेश मसाला अपने बड़े पुत्र के विवाहोपरांत शुक्रवार की शाम को आयोजित प्रीति भोज में 101 गरीब, निराश्रित एवं असहाय कन्याओं के विवाह हेतु 1 लाख 51 हजार रुपए का चेक प्रदान करते हुए कहा कि आज से मेरी स्वयं की दो बेटियों के साथ यह 101 बेटियां और जुड़ गई । अब मेरे 103 बेटियां हो गई। जिनके पूरे जीवन की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं।

उल्लेखनीय है कि देश के नामी मसाला व्यवसाई राजेश मसाला के बड़े पुत्र हिमांशु अग्रहरि की बाइट 24 नवंबर को कानपुर के बड़े व्यवसाय की पुत्री के साथ राजस्थान में विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद राजेश मसाला की बहू घर आई। राजेश मसाला ने बड़ी बहू के घर आगमन की खुशी में 28 नवंबर को रिसेप्शन पार्टी रखी थी। इसी दौरान देर शाम उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के हाथों 101 गरीब एवं निर्धन परिवार की बेटियों को 1 लाख 51 हज़ार रुपए का चेक प्रदान किया गया। यह बेटियां सिर्फ अमेठी जनपद की ही नहीं बल्कि आसपास के जनपदों की है। जिनकी मदद राजेश मसाला परिवार के द्वारा किया गया। इस मौके पर राजेश मसाला ने बताया कि 51 हज़ार रुपए विवाह में भोजन आदि के खर्च हेतु और 1 लाख रुपए गृहस्थी बसाने के लिए सभी को दिया गया है। अब तक मेरी दो बेटियां थी। आज से यह 101 बेटियां भी मेरी हो गई। अब मेरे 103 बेटियां हो गई जिनकी पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। आज ही नहीं भविष्य के पूरे जीवन में उनके दुख सुख में मैं सहभागी रहूंगा। इस मौके पर मुंबई से चलकर आए गायक कैलाश खेर ने अपने गीतों से शमा बांध दिया।

राजेश मसाला के द्वारा किए गए इस अभूतपूर्व कार्यक्रम की चर्चा लोगों की जुबान पर है। उन्होंने सीधे तौर पर 1 करोड़ 52 लाख 51 हज़ार रुपए दान कर संपूर्ण समाज को संदेश दिया कि अगर ऊपर वाला आपको सक्षम बनाता है तो निश्चित रूप से गरीब, लाचार, असहाय और निराश्रित लोगों की मदद जरूर करनी चहिए।

इस रिसेप्शन पार्टी में उत्तर प्रदेश सरकार की परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, नरेंद्र कश्यप, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजय सिंह, बृजभूषण शरण सिंह, एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी, एमएलसी व प्रदेश महामंत्री गोबिन्द नारायण शुक्ला ''राजा बाबू'', एमएलसी शैलेन्द्र प्रताप सिंह, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह , अयोध्या धाम के महापौर एवं कुलगुरु गिरीशपति त्रिपाठी सपत्नीक मौजूद रहे। इसी के साथ तमाम उद्योगपतियों का भी जमावड़ा लगा रहा।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के छात्र ने प्रतियोगिता में मंडल स्तर के लिए किया क्वालीफाई

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

बांदा। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा आयोजित जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय हरदौली ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है। शुक्रवार को हुई प्रतियोगिता में विद्यालय के छात्र आयुष ने अपने उत्कृष्ट विज्ञान मॉडल के दम पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। जीत के साथ आयुष को 5000 रुपये की धनराशि और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इसी के साथ आयुष ने मंडल स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बांदा में आयोजित इस प्रतियोगिता में सीबीएससी, आईएससी और उत्तर प्रदेश बोर्ड के कुल 44 विद्यालयों ने प्रतिभाग किया। विद्यालय के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में यह 52वीं उपलब्धि है, जो विद्यार्थियों की बढ़ती वैज्ञानिक समझ, विद्यालय के मजबूत शैक्षिक वातावरण और शिक्षकों के समर्पित निर्देशन को प्रमाणित करती है। समाज कल्याण उपनिदेशक जे. राम ने शनिवार को बताया कि यह उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों को भी वैज्ञानिक सोच की ओर प्रेरित करेगी।

गोआश्रय स्थलों पर ठंड से बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए: जिलाधिकारी

औरैया। जिलाधिकारी डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने शनिवार को जूम मीटिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि गोआश्रय स्थलों पर संरक्षित गोवंश को ठंड से बचाव के लिए टाट, पट्टी, फूस, अलाव सहित सभी आवश्यक सुविधाएं समय से उपलब्ध कराई जाएं। इसके लिए ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों व संबंधित अधिकारियों को सक्रिय रूप से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। जूम मीटिंग में जिलाधिकारी ने छात्रवृत्ति फीडिंग की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि संबंधित संस्थानों से संपर्क कर प्री-मैट्रिक व अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रवृत्ति का डेटा तत्काल अपलोड कराया जाए, जिससे पोर्टल पर प्रगति दर्ज हो सके। जिलाधिकारी ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में बताया कि 30 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी बूथवार भ्रमण कर अवशेष कार्य पूर्ण कराएं। सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए गए कि प्रातः नौ बजे से सायं पांच बजे तक अभियान में सक्रिय रहकर दिन के अंत में तहसील पहुंचकर शेष कार्य निपटाएं। जिलाधिकारी ने आमजन को यह भी अवगत कराने के निर्देश दिए कि एक से अधिक स्थान पर गणना प्रपत्र भरने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एसआईआर से संबंधित किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए कंट्रोल रूम टोल फ्री नंबर 1950 व 05683-249533 पर संपर्क किया जा सकता है।